RNI NO. RAJHIN/2013/57419

राजस्थान का सर्वाधिक ई-पेपर दैनिक

द पुलिस पोस्ट

अंदोलन नहीं अखबार

जयपुर
बुधवार
24 जुलाई, 2024

वर्ष: 10: अंक: 99

जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा से प्रसारित

दूरभाष: 01482: 433184: पृष्ठ: 08: मूल्य: 1.50 रुपए

बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 वीं बार किया बजट पेश

केंद्रीय बजट में राहतों की सौगात, राजस्थान को नया औद्योगिक प्रोजेक्ट

सोना, चांदी, मोबाइल, चार्जर, बिजली के तार सस्ते

प्लास्टिक की चीजें, सोलर पैनल महंगे

द पुलिस पोस्ट/नई दिल्ली

केंद्र की मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का मंगलवार को पहला बजट पेश किया जो बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को कम करने में मददगार साबित होगा। साथ ही किसानों, महिलाओं, युवाओं को भी राहत की बात बजट में की गई है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इस बजट में राजस्थान को भी नया औद्योगिक प्रोजेक्ट देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। सीतारमण ने अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवा, गरीब, महिला और अन्नदाताओं को ध्यान मे रखते हुए विशेष नौ सूत्रीय योजनाओं का एलान किया। बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद मुहैया कराने की घोषणा की है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं को भी मामूली राहत दी है।

अन्नदाताओं पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

महिलाओं और बालिकाओं का भी रखा ध्यान

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाए जाएंगे।

सर्विस सेक्टर के लिए क्या

बजट में निजी क्षेत्रों को सरकारी योजनाओं के जरिए मदद दी जाएगी। वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनियों को 3.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए योजना लाने का एलान किया है।

बजट के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही, वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी।

इन चीजों को महंगा करने का एलान

वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है।

जरूरतमंद लोगों को मिलेगा पक्का घर

तीन करोड़ गरीब परिवारों व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे।

युवाओं के सपने को लगेंगे पंख

केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।

एजुकेशन लोन में छूट

जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 लाख रुपये से ज्यादा का एजुकेशन लोन मिलेगा। लोन का 30 फीसदी तक पैसा सरकार देगी।

टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप

इसके साथ ही सरकार 500 शीर्ष कंपनियों एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इस योजना में 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।

पहली नौकरी वालों के लिए

पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए एक लाख रुपये से कम सैलरी होने पर 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में दी जाएगी।

मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई।

पर्यटन प्रोत्साहन भी जारी

बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।

वेतन भोगी कर्मियों को राहत

नए टैक्स रिजीम में 3.75 लाख तक तक की इनकम टैक्स फ्री, 17.5 हजार रुपये का फायदा।

फैमिली पेंशन पर भी टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 25 हजार

वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 10 से 12 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 20 फीसदी और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।

टैक्स कटौती में हुआ बदलाव

आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया गया। पहले यह कटौती 15,000 रुपये थी। वहीं, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रावधान किया गया।

शेयर बाजार के निवेशकों को लगा झटका

बजट भाषण में जहां एक तरफ न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी घोषणा की गई हैं। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़े एलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को को 12 फीसदी कर दिया गया। पहले यह 2.50 फीसदी था। वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 20 फीसदी कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े एलान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला।

रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बजट

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी।

बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष मदद

बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की मदद देने का एलान किया गया। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल मे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम लॉन्च करने की बात कही गई।

पटना से लखनऊ सिर्फ 6 घंटों में

साथ ही पटना से लखनऊ पांच से छह घंटे में पहुंचा जा सकेगा। भागलपुर से लखनऊ आठ से नौ घंटे में जाना संभव होगा। बक्सर को चार लेन की सडक़ और दो-दो लेन के दो नए पुलों के सहारे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोडऩे पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। इनमें दो लेन का एक पुल बीते वर्ष बनकर तैयार होने के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया था। अब यहां दो लेन का एक और पुल बनाने की तैयारी है। बक्सर में इन दोनों के अलावा 1977 का बना एक और दो लेन पुल चालू हालत में है। हालांकि इस पुल के कमजोर हो जाने के कारण इस पर केवल हल्के चारपहिया और दोपहिया का ही आवागमन होता है। मौजूदा दोनों पुल एक-दूसरे से बिल्कुल सटकर बनाए गए हैं। तीसरा पुल भी इनके ठीक बगल में ही बनेगा। इस तरह बक्सर में गंगा पर तीन पुल हो जाएंगे। इनमें से नए वाले दोनों पुल के जरिए बक्सर-पटना एनएच 922 और भविष्य में बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव हो जाएगा।

भरौली में बन रही 17 किमी लंबी सडक़

बक्सर को इस हाईवे से जोडऩे के लिए लगभग 17 किलोमीटर लंबी फोरलेन सडक़ भरौली से बन रही है। इसी सडक़ के जरिए बिहार के वाहन भविष्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। इसके लिए गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर के पास इंटरचेंज प्वाइंट बनाया जा रहा है। करीब 350 किलोमीटर होगी एक्सप्रेसवे की लंबाई बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे होना और डीपीआर बनना अभी शेष है। बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को फिलहाल केंद्र से मंजूरी मिलने की औपचारिकता शेष है। केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद उम्मीद जगी है कि इसके लिए सर्वे जल्द शुरू होगा। सर्वे पूरा होने के बाद ही इस मार्ग की लंबाई और दिशा स्पष्ट होगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि यह मार्ग 350 किलोमीटर के करीब लंबा होगा।

बजट में राजस्थान को भी कई प्रोजेक्ट मिले, सीएम भजनलाल ने बताया विकासोन्मुखी बजट

जयपुर। केंद्रीय बजट में राजस्थान को नया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देने की घोषणा की गई है। इसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। राजस्थान को केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी से 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को फायदा होगा। कृषि क्षेत्र में राजस्थान दाल का बड़ा उत्पादक है। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा की है। इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया। इसका बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा। 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। इससे प्रदेश के युवाओं को भी फायदा मिलेगा। जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये 1578 एकड़ जमीन में विकसित किया जाएगा। इस पर 922 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिख रही थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी JPIMA को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे थे। राज्य सरकार ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट के वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 275 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के पास विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जोधपुर और पाली शहर से बराबर दूरी 30 किलोमीटर पर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लाइन पर मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है। केंद्र से राजस्थान को इस बार टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीतारमण की ओर से पेश बजट में स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में यह जानकारी दी गई है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 66,556 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस साल इस राशि में करीब 7 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत है। जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी की मंडी भी कहा जाता है। सूरत के बाद जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी का बड़ा बाजार है। बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6 प्रतिशत की गई है। इसका सीधा फायदा जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को होगा। जयपुर में हर साल करीब 5 हजार करोड़ का सोना-चांदी इंपोर्ट होता है। कस्टम ड्यूटी घटने से इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा।

मेले पर रोक लगाने की उठी मांग फिर एक बार शुरू हुआ ज्ञापन का दौर

व्यापारियों में तीन-तीन पनपता जा रहा आक्रोश, न्याय नहीं तो लेंगे व्यापारी न्यायालय की शरण

व्यापारी बोले ना राज्य मंत्री सुनने को तैयार ना सांसद, अब आखिर जाएं तो कहां

शिवगंज नगर पालिकाध्यक्ष कांग्रेस से है पालिका अधिकारी ने स्वीकृति प्रदान की है तो पालिकाध्यक्ष को अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए ..

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज – शहर के महाराजा मैदान में आयोजित होने वाला फेस्टिवल लगातार सुर्खियों में आ रहा नजर, जिसे लेकर स्थानीय व्यापारियों ने 19 जुलाई शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप उक्त मेले की स्वीकृति निरस्त करवाने की मांग उठाई थी लेकिन उसके बावजूद बाहरी व्यक्ति के द्वारा मेला लगाने को लेकर तैयारियां जोरों पर देखते हुए उक्त मामले को लेकर व्यापारियों ने बताया कि हमारे द्वारा राज्य मंत्री एवं सांसद दोनों को ही फोन के माध्यम से अवगत करवाया गया लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होता देखकर हमारे द्वारा निम्नांकित 8 मांगो का लिखित ज्ञापन तैयार कर मेल के माध्यम से केंद्र एवं राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधियों एवं आला अधिकारियों को भेजा गया । तत्पश्चात मंगलवार की सुबह व्यापारियों ने एकजुट होकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के निवास स्थान पहुंचकर पूर्व विधायक को मामले से अवगत करवाया एवं निवेदन करते हुए मांग की की अगर यह मेला लगता है तो स्थानीय व्यापारियों के घर का पालन पोषण तक करना मुश्किल हो जाएगा, व्यापारियों को पूर्व विधायक लोढ़ा के आश्वासन के बाद एक सुखद अनुभूति का आभास महसूस हुआ । व्यापारियों ने पत्र के माध्यम से अवगत करवाया की कुछ दुकान किराए की तो कुछ दुकान स्वयं की है वही हम व्यापारी जीएसटी सहित टैक्स भरते हैं, कुछ दिन पहले मनोरंजन मेला के नाम पर एक बाहरी व्यक्ति ने उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका से महाराजा मैदान में मेले के रूप में व्यापार के लिए दुकान लगाकर व्यापार हेतु अनुमति मांगी जिसको नगर पालिका ने मात्र उस व्यक्ति से यह शुल्क भरवाया की महाराज मैदान की साफ-सफाई एवं फायर की गाड़ी उपलब्ध करवाने हेतु रसीद काटी, उपखंड अधिकारी ने भूमि की किस्म की रिपोर्ट तहसीलदार शिवगंज से लिए बिना ही भूमि पर मेला लगाने की अनुमति दे दी जबकि खसरा संख्या 89/90 भूमि का वर्गीकरण किस्म कृषि भूमि पड़त है, कृषि भूमि का बिना भु उपयोग परिवर्तन किए कृषि भूमि पर व्यापार करने की एनओसी देना न्योयाचित नहीं है। जिसका उपखंड अधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया एवं दिनांक 16 जुलाई को मेला व्यापार लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई । इस बात को लेकर हम सभी व्यापारीगण जब उपखंड अधिकारी को मिले तो एक लोक सेवक होते हुए उन्होंने व्यापारी को कहा कि मैंने एनओसी दे दी है लेकिन उन्होंने जो नगर पालिका में जमा करवाया है वह तुम व्यापारी तुम्हारे जब से दे दो जबकि हम फरियाद लेकर जाए तो किसके पास, व्यापारियों ने बताया कि आगे तो बिना सीजन के हम लोग बैठे हैं स्टाफ की सैलरी तक देना भारी पड़ रहा है उसे पर भी यदि बिना बिल के माल खरीद कर कम दाम पर ग्राहक को यदि मेला लगाकर बेचने लगेंगे तो हमारे पास कौन ग्राहक आएगा, व्यापारियों ने बताया कि दुकान के भरोसे ही हमारे परिवार का पालन पोषण बच्चों की पढ़ाई होती है । व्यापारियों ने मांग करी की 16 जुलाई को उपखंड अधिकारी के द्वारा दी गई स्वीकृति को अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर शहर के 500 लघु उद्योग व्यापारियों को राहत प्रदान करवाई जाए । इस दौरान जितेंद्र सिंह राव, धमार्राम, रुपेश सोनी, बाबूलाल, भरत कुमार विक्रम सहित कई व्यापारी उपस्थित रहे ।

क्या कहना है इनका

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की बात को लेकर हम व्यापारी सभी संतुष्ट हैं, मेरे द्वारा सांसद कों भी फोन कर महाराजा मैदान में लगने वाले फेस्टिवल को लेकर अवगत करवाया गया था।

रूपेश सोनी, व्यापारी -शिवगंज

इस तरह के फेस्टिवल लगने से स्थानीय व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, मेले के व्यापारी घटिया माल सस्ती दर में बेचते हैं जिसे स्थानीय लोग खरीद कर ले जाते हैं जिसके चलते व्यापारियों को भी नुकसान एवं आमजन को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है ।

नारायण सिंह , अध्यक्ष - मोबाइल एसोसिएशन, शिवगंज

हम व्यापारियों के साथ है अगर मेला लगने से व्यापारी को नुकसान होता है तो मामले को लेकर मंत्री जी से बात कर कर व्यापारियों को अवगत करवाया जाएगा ।

ताराराम कुमावत, अध्यक्ष - भाजपा नगर मंडल शिवगंज

फेस्टिवल को लेकर शहर में कुछ दिनों से विवादित माहौल बना हुआ है, व्यापारियों की भावना को ध्यान में रखते हुए उपखंड प्रशासन को समय रहते हुए मेले के लिए दी गई स्वीकृति को निरस्त कर व्यापारियों को राहत प्रदान करनी चाहिए ।

कुन्दनमल राठी, भाजपा नगर मंडल महामंत्री - शिवगंज

शहर में लगने वाले फेस्टिवल का में पूर जोर विरोध करता हूं। ऐसे फेस्टिवल लगने से में ग्राहक नहीं आतें हैं। जिसके चलते व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ता है ।

पार्षद लक्ष्मण परिहार, व्यापारी -शिवगंज

शहर में कांग्रेस के राज में 5 साल तक कोई मेला नहीं लगा था, लेकिन भाजपा राज में मेला लगने से व्यापारियों की भावनाएं आहत हो रही है। प्रशासन को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ।

प्रकाशराज मीणा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष

अभी नगर पालिका में बोर्ड कांग्रेस पार्टी का है अगर नगर पालिका अधिकारी ने स्वीकृति दी है तो पालिकाध्यक्ष को अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों का साथ देना व व्यापारियों के खिलाफ जाना पार्टी के हित की बात नहीं है इन पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए सीमादेवी माली पूर्व प्रतिपक्ष नेता नगर पालिका मंडल शिवगंज

देश का बजट व भाजपा जिला महामंत्री ने की प्रसन्नता

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवा बजट पेश कर नया इतिहास रच दिया और बजट में देश की आमजनता को अनेको राहत प्रदान की इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल ने बजट की सराहना करते हुये बताया कि भारत की आर्थिक प्रगति सही रास्ते पर है। भारत की महंगाई कम, स्थिर है। भारत में महंगाई दर 4% के लक्ष्य की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी हालत में। सरकार का फोकस गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर है। सरकार का फोकस रोजगार पैदा करने के मौकों पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणन ने सुबह 11 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू कर किया। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मोदी पर भरोसा

जताते हुए उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। हम इसके लिए हम आभारी हैं। हम हमारी नीतियों पर भरोसा जताने के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हैं। वित्त मंत्री ने बजट मे खेती में उत्पादकता ,रोजगार और क्षमता विकास समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय ,विनिर्माण और सेवाएं शहरी विकास ऊर्जा सुरक्षा, अधोसरंचना नवाचार, शोध और विकास अगली पीढ़ी के सुधार आएगा भारत की आर्थिक प्रगति सही रास्ते पर है। सरकार का फोकस गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर है। सरकार का फोकस रोजगार पैदा करने के मौकों पर है।मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ की गई: एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता: पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए वित्त मंत्री ने 10 लाख करोड़ रुपये का एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने ,रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी। एक करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया गया है। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रस्ताव किया गया है। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे

पुलिस थाना रायपुर द्वारा 6 ट्रेक्टरों मय ट्रॉलीयों को कोठारी नदी से अवैध बजरी खनन मे डिटेन किये गये

द पुलिस पोस्ट

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा श्री राजन दुष्यन्त आईपीएस आदेषानुसार श्री रोषन पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाडा भीलवाडा व श्री रितेष कुमार वृताधिकारी वृत्त गंगापुर के निकटतम सुपरविजन में थाना क्षेत्र की कोठारी नदी से लगातार हो रहे अवैध बजरी खनन रोकथाम हेतु श्री राजेन्द्र सिह उ.नि. थानाधिकारी रायपुर के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा कार्यवाही कर अवैध बजरी खनन व परिवहन करते कुल 08 ट्रेक्टर मय ट्रालियों मे 18 टन अवैध बजरी से भरे हुये को डिटने कर थाना रायपुर परिसर मे खडे कराये गये। टीम द्वारा की गयी कार्यवाही:- दिनांक 21.07.24 को थानाधिकारी राजेन्द्रसिह मय जाप्ता हैड कानि ओकारसिह 347, हैड भवानी सिह 491, हैड कानि घीसालाल 552, कानि सुनिल 304, कानि राजेश 924 कानि शेतानसिह 1524, चालक कानि महेन्द्र 1414 द्वारा रात्रि गस्त के दौरान कोठारी नदी से अवैध बजरी खनन करते हुये कुल 06 ट्रेक्टर मय ट्रालियो मे अवैध बजरी भरी हुयी को व 02 ट्रेक्टर मय ट्रॉलियो मे अवैध बजरी भरी हुये को परिवहन करते हुये को डिटेन कर थाना रायपुर परिसर मे खडे कराये गये। अग्रीम कार्यवाही हेतु सुचना माईनिंग विभाग को दी गई। उक्त ट्रेक्टरो के चालक मौके से फरार हो गये।

नौकरी में नहीं ली छुट्टी फिर भी ले ली इंजीनियर की डिग्री राजस्थान में 32 अभियंताओं ने तो पदोन्नत तक ले ली

द पुलिस पोस्ट

जयपुर के दोनों निगम में भी ऐसे कई अभियंता लगे हुए हैं जो फजीर्वाड़ा कर नौकरी कर रहे हैं जयपुर स्वायत शासन विभाग के अधिकारियों की मिली भक्ति से कई कनिष्ठ अभियंताओं ने नौकरी में रहते हुए तीन वर्ष की इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली इस दौरान अधिकतर नौकरी से अवकाश तक नहीं लिया इनमें से कई अभियंता राजधानी के दोनों नगर निगम अलावा स्मार्ट सिटी जयपुर राजस्थान जोधपुर नगर निगम जेडीए में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं इनमें से अधिक अधिशासी अभियंता बन चुके हैं जबकि नियमों के मुताबिक सिविल में इंजीनियरिंग की डिग्री डिस्टेंस में लेने का प्रावधान ही नहीं है वर्ष 2013-14 की डीपीसी में भी कई डिग्री धारीओ अभियंता ऐसे हैं जिन्होंने बिना छुट्टी लिए 3 वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और डिग्री पड़ोसी के लिए लगा रखी है गौर करने वाली बात यह है कि समय-समय पर विभिन्न संगठन और डिग्री धारी के अभियंता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिल इसके बारे में अवगत कराते रहे लेकिन सुनवाई किसी ने नहीं की सूत्रों की मांने तो कुछ अभियंता तो ऐसे हैं जो उन लोगों में डिग्री लेकर आगे इसकी डिग्री मांगी ही नहीं इस डिग्री को सिविल रिकॉर्ड के शामिल कर पढ़ोतरी तक ले ली इन्हीं फर्जी डिग्री धारकों ने अधिशासी अभियंता बन गए एक्ट से डिग्री के लिए भी जरूरी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट ने सिविल इंजीनियर में डिग्री के लिए 75 हिस्ट्री क्लास में उपस्थित के अलावा लैब क्लास इंजीनियरिंग एग्जाम में उपस्थित भी अनिवार्य कर रखी है पर एक भी अभियंता उपस्थित नहीं रहे और फर्जी डिग्रियों पर

JRN Vidyapeeth Udaipur, Rajasthan.
IASE Gandhi Vidya Mandir, Sardarsahar , Rajasthan.
Allahabad Agriculture Research Institute, Allahabad (UP)
Vinayak Mission's Research Foundation, Salem (Tamil Nadu)

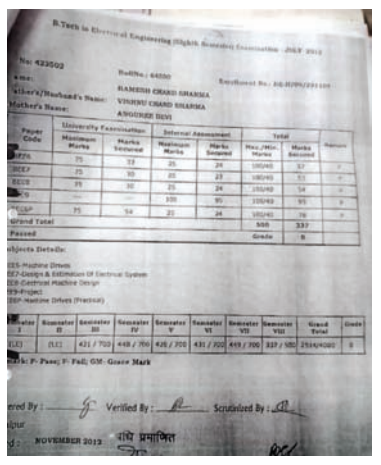

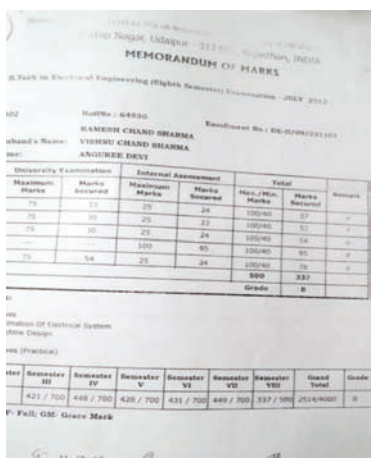

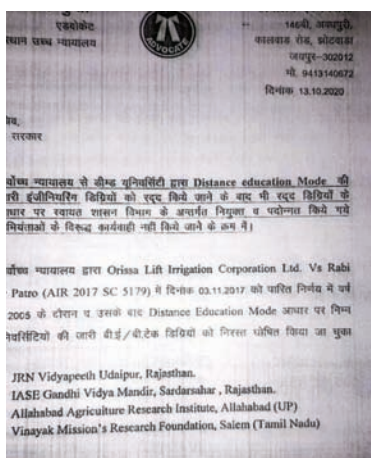

इन्होंने पूरी नौकरी कर ली है ऐसे कई अधिकारी रिटायरमेंट भी हो चुका है जिन्होंने राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपए फजीर्वाड़ा में उठाकर आनंद कर रहे हैं अपने बच्चों को विदेश में पढाई करवाना खुद फर्जी डिग्री पर लगे हुए हो सकता है कि उनके बच्चों की डिग्री भी फर्जी हो अनुपात भी जानबूझकर बिगाड़ा पिछली तीन भारतीयों की बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा में पहली बार 80 और 20 का अनुपात था दूसरी भर्ती में 85 और 15 का कर लिया तीसरी भर्ती में 52 से 48 का कर लिया इतना ही नहीं नियम विरोध जाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डिग्री तर्कों को फायदा पहुंचाया डिप्लोमा कार्य में एक पद्धति लेने के लिए डिग्री फर्जी ले ली और दूसरी क्रांति के लिए भी ले ली जबकि डिग्री धारक अभियंता का एक ही प्रमोशन नहीं हो पाया इसीलिए स्वायत शासन विभाग में पैसा लेकर कुछ भी फजीर्वाड़ा कर दो चलता है यहां पर कई सालों से जमकर बैठे यह अभियंता पैसा देकर नौकरी कर रहे इन अभियंताओं ने इंजीनियर की डिग्री लेने के लिए नौकरी में एक दिन की छुट्टी नहीं ली फिर भी बन गए अधिकारी रमेश चंद्र इंजीनियरिंग की फेक डिग्री धारक श्री रमेश चंद्र शर्मा एडिशनल अभियंता जयपुर नगर निगम ग्रेटर से स्वायत्त शासन विभाग में प्रमोशन लेकर खुद का रिटायरमेंट भी ले लिया राजस्थान सरकार का फर्जी डिग्री के आधार पर करोड़ों रुपया उठाकर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं रमेश चन्द शर्मा 17 साल में से इंजीनियरिंग में डिग्री धारक करते हैं तथा उक्त डिग्री के आधार पर अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता पदों पर विभाग की मिलीभगती से भेजो पदोन्नति प्राप्त करने में सफल हुए माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश दिनांक 3 - 11- 2017 द्वारा श्री शर्मा की कथित डिग्री निरस्त हो चुकी है इस स्थिति में इन्हें फेक डिग्री के आधार पर दी पड़ोसी के करने के स्थान पर उन्हें विभाग का ही मुख्य अभियंता ऊर्जा बचत स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त बनाना में आश्चर्यजनक है राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य को उनके ज्ञान से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है इसके विपरीत राज्य के किस विभाग की छवि खराब हुई है रमेश चंद शर्मा को मुख्य अभियंता ऊर्जा बचत स्वास्थ्य शासन विभाग स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान का अतिरिक्त कार्य भार पास ऑफिस जाने 99 पर पूर्ण विचार करना तो दूर की बात है इन्होंने इसका रिक्वायरमेंट भी वहीं से किया डबल डबल सरकारी फायदा उठाया पूर्व में भ्रष्टाचार ब्यूरो जयपुर में भी इन फर्जी डिग्री तारीखों के लिए पत्र लिख चुके हैं जो इस रमेश चंद शर्मा की डिग्री लगी हुई है कुल 32 कर्मी ऐसे है जिसने फर्जी डिप्लोमा पर डिग्री पर नौकरी की है ऐसे ही सैकड़ो और कर्मी भी है जो स्वायत्त शासन विभाग में सफाई निरीक्षक के पद पर आज भी नौकरी कर रहे हैं इन सभी डिप्लोमा धारियों व डिग्री कार्यों की नौकरी की जांच कर इन्हे जेल भेजना चाहिए ना कि इनका प्रमोशन करना चाहिए ऐसे ही यह रवैया चला रहा तो राजस्थान सरकार डूबते वक्त नहीं लगेगा क्योंकि यह फर्जी डिग्री तारक डिग्री उठा देते हैं ऐसे ही पांच कॉलेज में फर्जी डिप्लोमा दिए गए हैं जो आज भी चल रहे हैं तीस हजार मे फायर पचास हजार मे एएसआई व एक लाख मे अन्य डिप्लोमा पाच लाख मे डिग्री मिल जाती उसके दलाल भी स्वायत शासन विभाग निर्देशक के मुख्यालय मे आज भी बैठे है

नगर परिषद के पूर्व आयुक्त योगेश आचार्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नगर परिषद के अधिवक्ता को लिखा गया पत्र

द पुलिस पोस्ट

सिरोही। राजीवनगर आवासीय योजना की जमीन पर सिरोही के मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब लोगों को बेदखल करने के लिए डेढ़ दशक से एक संगठित समूह काम कर रहा है।

इसमें कई लोगो की भूमिका समय समय पर सामने आई है।

प्रशासन के इन लोगों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाने के कारण इनके हौसले टूट नहीं रहे हैं। ये बात अलग है कि एक ही तरह के मामले में बार बार मुंह की खाने के बाद भी किसी संशोधित प्लान की जगह उसी प्लान की पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं। सबगुरु न्युज के पास वो ताजा पत्र भी आ चुका है जिसे लेकर वर्तमान में बवाल मचा हुआ है।

इस पत्र की ताबीर और इसमें इस्तेमाल कानूनी शब्दावली स्पष्ट बता रही है कि इस पत्र पर हस्ताक्षर भर आयुक्त के हैं, इसकी जुबान किसी कानून के जानकार की है। अब ये कानून का जानकर नगर परिषद से ही जुड़ा हुआ है या बाहर का है ये जांच का विषय है। वैसे लोगों को सबसे ज्यादा संदिग्ध उन नेताओ की चुप्पी लग रही है जो नगर परिषद में हवा भी चल जाए तो उसकी सूचना तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन सबगुरु न्युज द्वारा 20 जुलाई को इस मामले के खुलासे से पहले आठ महीने से इस मुद्दे पर चूं तक नहीं की।

नगर परिषद के अधिवक्ता को ये लिखा था

नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त योगेश आचार्य के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में राजीव नगर आवासीय परियोजना के नगर परिषद के अधिवक्ता को केस विड्रा करने के लिए जो पत्र लिखा उसमे 6 बिंदु थे। इस पत्र में बिंदुवार लिखा कि

1. राजीव नगर आवासीय योजना की एसएलपी वाली भूमि को इकरारनामा दिनांक 16.11.1989 एवं संलग्न विक्रय विलेख 253/1989 (निष्पादन दिनांक 27.03.1989 एवं पंजीयन दिनांक 06.05.1989) के जरिये पूर्व में नगर पालिका की योजना के लिए ली गई थी। लेकिन एससी से गैर एससी / संस्था के इस सौदे में कानूनी प्रावधानों के उल्लघंन के कारण आज भी इस भूमि में एससी खातेदार कायम रहा है। राजस्व रिकार्ड के ऑनलाईन जमाबंदी में भी एससी पक्षकार का नाम ही कायम है। खातेदारी विवाद होने पर रकम वापस लौटाने की विक्रय, पेरा 4 में शर्त थी एवं योजना व उसके आवेदन वगैरह भी प्रभावी नहीं रहे है।

2. यह कि उक्त कृषि भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42ख व उसके संशोधन दिनांक 01.05.1964 के विपरित जाकर तत्कालीन नगर पालिका सिरोही संस्था के नाम खरीदने से एससी से गैर एससी का सौदा व संबंधित समस्त दस्तावेजात प्रारम्भ से विधि शून्य रहे है। जिसको किसी न्यायालय से शुन्य की घोषणा कराने की आवश्यकता नहीं है। जो न्यायालय संबंधित प्रभारी तत्कालीन प्रभावी उपखंड अधिकारी सिरोही के एक विधि स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक रीडर/रिट/2008/189 दिनांक 31.10.2008 में स्पष्ट किया गया है। साथ ही राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप-6 के द्वारा दिशा-निर्देश पत्रादेश दिनांक 13.11.2006 जारी करके नगर परिषद् नाम के सभी भूमि नामांतरण निरस्त करा दिये थे। एससी की इस कृषि भूमि में पूर्ववत एससी को ही कायम रखकर इस भूमि प्रकरण को एससी के पक्ष में सरकार ने पुर्णतयाः निस्तारण कर दिया था।

3. यह कि उक्तानुसार उक्त कृषि भूमि के सौदे व दस्तावेजों की महत्ता विधि शून्य हो जाने, राज्यादेश परिपत्र/कानूनी प्रावधान / न्यायिक निर्णय सबकुछ एससी के पक्ष में होने से नगर परिषद् सिरोही ने दिनांक 03.10.2013 को एससी पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है। जिसमें एससी पक्ष को स्वतंत्र हक देने के लिए इस भूमि से हक त्याग करने एवं एससी पक्षकार से पूर्व की संपूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि व ब्याज पुनः लेकर सौदे संबंधित सभी दस्तावेजों को निरस्त करने, सभी वाद विवादों, अपील वगैरह विड्रो/समाप्त करने, अतिक्रमण हटाने व प्रकरण का पुर्णतया निस्तारण किये जाने इत्यादि जैसे सभी आवश्यक व महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत निर्णय पारित किये है।

4. यह कि एससी की कृषि भूमि संस्था भी नहीं ले सकती है, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एसएलपी संख्या अस्था भी नहीं ले सकती है, जिसके लिए बनाम अण्जनेय ऑर्गेनिक हर्बल प्रा. लिमिटेड या 6741-6742/2012 (राजस्थान राज्य सामन्या का हवाला देते हुए राज्य सरकार के राजस्वाति निर्णय दिनांक 20.0002 परिपत्र क्रमांक 37 राज-7/2010 दिनांक 05.02.2013 पुजारीद्वारा स्पष्टीकरणात राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप-8 द्वारा भी एससी पक्ष को कानूनी प्रावधानों, जारी राजकीय परिपत्रों-राज्यादेशों पर न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए एससी की कृषि भूमि एससी के पास ही कानूनी तौर पर कायम कराने / कायम रखने के लिए राज्यादेश क्रमांक प.6 (54) राज-6/2001 दिनांक 30.05.2022 (संलग्न) में सभी निर्देश जारी किया है। साथ ही सरकार भी रा.का.अधि. की धारा 175 में एससी की कृषि भूमि आवंटन रूल्स-1970, धारा 6 (3) में भी स्पष्ट किया गया है.

5. यह कि उपरोक्तानुसार कानूनी प्रावधानों, राजकीय आदेशों व पारित प्रस्ताव की पालना करके एससी पक्षकार से रकम वापस लेने का तब नगर परिषद् ने सुचना मांग-पत्र क्रमांक नपसि/5288 दिनांक 31.12.2013 को जारी किया था, जिस पर एससी पक्षकार द्वारा दिनांक 06.01.2023 को जमा कराई गई पूर्व सौदे की मुल विक्रय प्रतिफल राशि रुपए 7 लाख 39 हजार 200 को नगर परिषद् ने प्राप्त कर ली है। साथ ही हाल में इस मुल विक्रय प्रतिफल राशि को 34 वर्षों तक नहीं चुकाये जाने का प्रस्तावानुसार ब्याज 9% दर से रुपए 22 लाख 62 हजार 000 का नगर परिषद् सिरोही द्वारा जारी मांग पत्र क्रमांक 5575 दिनांक 17.11.2023 का भुगतान भी एससी पक्षकार से चैक (कैनरा बैंक) द्वारा नगर परिषद् सिरोही ने प्रस्तावानुसार प्रकरण निस्तारण हेतु आपसी करार दिनांक 26.11.2023 को निष्पादित करके दिनांक 27.11.2023 को नोटेरी करा दिया है।

6. यह कि 34 वर्ष में एससी की कृषि भूमि किसी भी तरह गैर एससी / संस्था के नाम नहीं हो सकी। इस भूमि के दस्तावेज / प्रकरण निरस्तीकरण व निस्तारण से नगर परिषद् को बकायदा आर्थिक फायदे/आय भी अत्यधिक होगी। उक्त करार एवं पारित प्रस्ताव दिनांक 03.10.2013 के अनुसार एससी की इस भूमि का एससी के हक में ही निस्तारण कराने का है। जिसके लिए प्रार्थी पक्षकार नगर परिषद् के द्वारा आप अधिवक्ता को सभी संलग्न उक्त दस्तावेज व प्रपत्र भेजकर लेख है कि उक्त एसएलपी का विड्रो/निस्तारण हेतु इस अभ्यावेदन एवं संलग्नक दस्तावेजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर अग्रीम कार्यवाही व औपचारिकताएँ पूर्ण कराने का श्रम करावे, ताकि माननीय न्यायालय से प्रकरण का उचित निस्तारण किया जा सके।

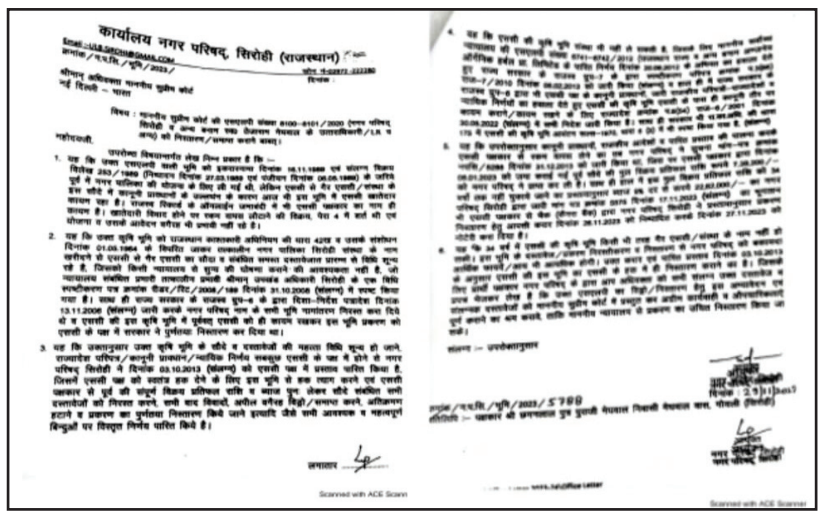

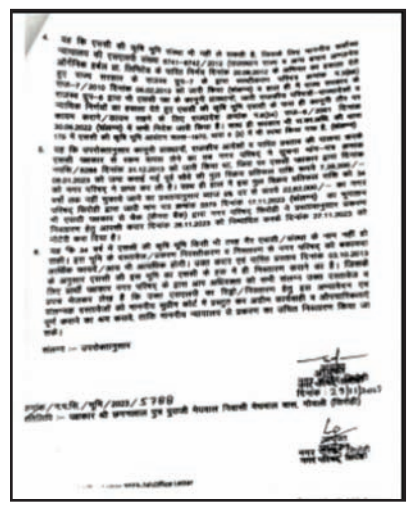

कार्यालय की रक्षित प्रति की बजाय दी प्रतिद्वंदी को प्रतिलिपी

पत्र की भाषा स्पष्ट रुप से बता रही है कि उनकी मंशा सिरोही के लोगों को ही नहीं राजस्थान सरकार को भी धोखा देने की रही। इसमें सरकार के पक्ष के किसी भी बिंदु का जिक्र नहीं किया गया। यही नहीं इस पत्र में की है एक हरकत तो स्पष्ट बता रही है। कि आयुक्त ने इस काम को प्रतिवादी के हित का हित साधने के लिए किया है। इस पत्र को उच्चतम न्यायलय में नगर परिषद के अधिवक्ता को लिखा गया था। ये आधिकारिक अंतर विभागीय पत्र था। लेकिन, इसकी प्रतिलिपि प्रतिवादी को दी भी दी गई थी। ये पत्र के अंत में लिखा हुआ है। लेकिन इसकी कार्यालय को रक्षित प्रतिलिपि का जिक्र नहीं है। इसका मतलब नियमानुसार जो सबसे जरूरी था वो कार्यालय प्रतिलिपि रखी नहीं गई जो आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है।

फिर हुआ सिरोही के साथ धोखा, करोडों की जमीन खुर्दबुर्द करने की कोशिश

केन्द्र सरकार का बजट पारित आम जनता को राहत भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष की जुबानी

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज । एनडीए सरकार व देश की लगातार दूसरी बार बनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार सातवा बजट पेश कर नया इतिहास रचा। बजट में देश की आमजनता को अनेको अनेक राहत प्रदानकी गई ।इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शिवगंज के मंडल अध्यक्ष तारा राम कुमावत वह महामंत्री कुंदनमल राठी ने बजट की सराहना करते हुये कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति व सही रास्ते पर होने से भारत की महंगाई में कम होने से महंगाई दर 4% के लक्ष्य की ओर है।

सरकार का फोकस महिलाओं, किसान व गरीबों और युवाओं पर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणन ने सुबह 11 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। हम इसके लिए हम आभारी हैं। हम हमारी नीतियों पर भरोसा जताने के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हैं।

वित्त मंत्री ने बजट मे खेती में उत्पादकता ,रोजगार और क्षमता विकास,

समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय ,विनिर्माण और सेवाएं शहरी विकास

ऊर्जा सुरक्षा,अधोसरंचना शोध और विकास अगली पीढ़ी में सुधार आएगा। सरकार का फोकस युवाओं के रोजगार पैदा करने के लिए तत्पर है।

मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ की गई। एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ताः पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए वित्त मंत्री ने 10 लाख करोड़ रुपये का एलान किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने ,रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी। एक करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया गया। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रावधान किया गया है।

पुलिस थाना कारोई द्वारा अवैध बजरी परिवहन करते हुए

एक डम्पर व एक ट्रेक्टर मय ट्रोली जब्त।

कुल 34 टन अवैध बजरी जब्त।
आरोपी बाबु लाल भील व अशोक कंजर गिरफतार।

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा श्री राजन दुष्यन्त आईपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाडा श्री रोषन पटेल जी आरपीएस के निर्देशन व वृताधिकारी गंगापुर श्री रितेष कुमार जी के निकटतम सुपरवीजन में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे विषेष अभियान के तहत अवैध बजरी परिवहन एवं अवैध खनिज मिट्टी दोंहन की रोकथाम हेतु थाना कारोई टीम द्वारा अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक डम्पर मय 30 टन बजरी एवं एक ट्रेक्टर ट्रोली मय 04 टन बजरी के जब्त कर दोनो वाहनो के चालको को किया गिरफतार। घटना का संक्षिप्त विवरणः- इमरोज दिनांक 23.07.2024 को पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे विषेष अभियान के तहत अवैध बजरी परिवहन एवं दोंहन की रोकथाम हेतु थाना हाजा से थानाधिकारी द्वारा मय टीम के कडी मेहनत व लगन से कार्यवाही को अंजाम दिया जिसमे नौगावा चैराया थाना कारोई से अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक बिना नम्बरी डम्पर मय 30 टन बजरी एवं एक ट्रेक्टर ट्रोली मय 04 टन बजरी के जब्त की जाकर दोनो वाहनो के चालको को गिरफतार किया जाकर प्र.सं 128/2024 मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

महात्मा गांधी विद्यालय में बौरा दौड़ आकर्षण का केन्द्र रही: चौधरी

द पुलिस पोस्ट

शिवगंजः महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित खेलों के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता एंव शारीरिक एंव मानसिक विकास करने को लेकर छात्र-छात्राओं द्वारा पारम्परिक खेल बौरा दौड़ में बढ चढकर हिस्सा लेना विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती हेमलता चौधरी ने बताया कि स्कूल शिक्षा परिषद के निदेर्शानुसार खेल प्रभारी एंव शारीरिक शिक्षक धर्मेन्द्र गहलोत ने छात्र-छात्राओ का कक्षावार 50 मीटर बौरा दौड़ करवायी जिसमें प्रथम तथा द्वितीय कक्षावार कक्षा-10 कार्तिक एवं पियुष, तनीषा एंव

राधिका, 9 वीं में कुशाल एंव सौम्य, केवीन एंव जय, भाविका एंव मनस्विनी, कक्षा-8 में जितेन्द्र एंव मनीष, कनिषा अग्रवाल एवं आनिया, कक्षा 7 मोहित एंव आनन्द कुमार, रजंना एंव सुमित्रा, कक्षा-6 में रणवीर एंव मनोज, नीधी परमार एंव लक्षिता वैष्णव, कक्षा-5 में मनीष एंव शिवांश, अल्फिना एंव वैशाली, कक्षा-4 में खुशवीर भाटी एंव भव्य जानी, मीनाक्षी-वसुन्धरा आदी ने अच्छा प्रदर्शन किया। विशेषरूप से आकर्षण का केन्द्र अध्यापकों की बौरा दौड से बच्चों में हस्सी के भव्वारे फुट रहे थे। बौरा दौड़ में क्रमशः छगनलाल भाटी, महेन्द्रपाल परमार, धर्मेन्द्र गहलोत, रमेश कुमार, सुरजीत सिंह कविया ने भाग लिया जिसमें प्रथम व द्वितीय स्थान पर शारीरिक शिक्षक धर्मेन्द्र गहलोत व रमेश कुमार रहे।

परम पूज्य परमहंस योगीराज ब्रह्मलीन सद्गुरु देव श्री नित्यानंद का मैला वास्तानेश्वर महादेव मंदिर पहाड़ी पर

द पुलिस पोस्ट

सरूपगंज परम पूज्य परमहंस रसोसिद्ध योगीराज ब्रह्मलीन सद्गुरु देव श्री नित्यानंद जी (नंदबाबा, श्री सीताराम जी बाबा) कृष्णगंज गांव में स्थित श्री वास्तानेश्वर महादेव मंदिर पाठ स्थान एवं कृष्णगंज सरुपगंज सड़क किनारे स्थित गंगावेरी धाम समाधि मंदिर के ब्रह्मलीन सद्गुरु देव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत ओम नमो नारायण में हूं बडभागी पुरा मिलिया सद्गुरु देव नित्यानंद जी बाबा सद्गुरु देव श्री नित्यानंद जी (श्री सीताराम जी) बावजी प्रचार प्रसार तामझाम अमीर गरीब के भेदभाव से परे रहने वाले आबूराज में महान तपस्वी योगीराज हुए हैं मेरा सौभाग्य है और मे और मेरे जैसे हजारों लोग धन्य है जिन्हें हमें रसोसिद्ध योगीराज नित्यानंद बावजी का सानिध्य मिला सेवा और सन्मार्ग सुसंस्कार का मार्ग मिला सद्गुरु देव ने कभी भी भौतिक

सुखसुविओ को नजदीक फटकने नहीं दिया भीषण गर्मी में अधिकांश समय एक छोटी सी बिना लाइट पंखे वाली कोठरी मे ही तप साधना में लीन रहा करते थे कई बार छह सात दिनों तक कोठरी से बाहर नहीं आते थे बावजी ज्ञान गति और कर्म के अनुसार चलते थे कई बार देखने को मिला की बड़े से बड़े अधिकारी उधोगपति यहां तक कि पूर्व गृह मंत्री बुटासिह जैसे भी दर्शन करने आते थे घंटों इंतजार करते उनकी गति होती तो दर्शन देते नहीं तो अमीर गरीब छोटा बड़ा बिना दर्शन की लोटना पड़ता था ना कभी कोई गाड़ी रखीं कभी कहीं जाना होता तो भगत लोग जीप एम्बेसडर कार लेकर आ जाते थे वैसे तो बावजी ने लम्बे समय अतार्थ कितने ही वर्षो तक कभी कभार फलाहार ग्रहण करते थे जब उन्हें फलाहार करने की इच्छा जागृत होती थी उस समय भक्तगण सिंघाड़े राजगरे की रोटी बनाने लगते तो बावजी कहते भुख चली जाएगी उसके बाद किसको खिलाएंगे तब बावजी कहते की टोपले में पड़ी रोटी फलाहारी सब्जी पड़ी वो दे तो भक्त कहते बावजी वो सब्जी रोटी आठ दस दिन पुरानी है बावजी कहते भुख चली जाएगी फिर कौन खायेगा इसके बाद टोकरें में रखी एकदम सुखी लकडे जैसी और सब्जी पर लील और फुलन आने के बावजूद थाली में सुखी रोटी बासी सब्जी डालकर उसमें पानी मिलाकर घोल बना कर बावजी अपनी गति अनुसार ग्रहण कर लिया करते थे और ताजी बनीं फलाहार सब्जी रोटी फिर टोकरे में रख देते थे बावजी के आदेशानुसार गायों को सदैव चारा और ईसरा पामेरा कृष्णगंज समेत अनेक गांवों में प्रतिदिन गौ मां को घी तेल लगीं रोटी के साथ वापसी खिलाने का कार्यक्रम चलता रहता था बावजी के सानिध्य में ब्राह्मण देवता द्वारा विभिन्न यज्ञ पुजा पाठ अनुष्ठान के साथ भोजन प्रसादी चाय सोमवार को कुटंलो फलाहारी खिर प्रसाद जारी रहती थी लेकिन इतने कर्म चलने के बावजूद कभी किसी से पैसा नहीं मांगा जाता था अनवरत जारी रहता था हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर सद्गुरु देव गौ मुख वशिष्ठ आश्रम अबुर्दाचल आषाढ़ त्रयोदशी को वशिष्ठ आश्रम हजारों भक्तगणों के साथ पधारते और वशिष्ठ आश्रम गौमुख में तीन दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बिराजते एवं वहां सदियों पुराने अग्निकुण्ड में विद्वान ब्राह्मण देवता के जरिए वैदिक रिति रिवाज से हवन किया जाता था (यह वही ऐतिहासिक अग्निकुण्ड है जिनसे चार गौत्र के महापुरुषों की उत्पत्ति हुई थी) हजारों भक्तों के लिए महाप्रसादी का महा आयोजन हुआ करता है जिसकी पूर्ण व्यवस्था स्वयं महिला पुरूष भक्तगण सम्भालते थे आज भले ही सद्गुरु देव नित्यानंद बाबा लौकिक रुप से हमें दर्शन नहीं देते लेकिन अलौकिक रूप से उनका आशीर्वाद और उपस्थिति अप्रत्यक्ष अनुभूति करातीं है कल गुरु पूर्णिमा (व्यास पुजा) के पवित्र पर्व पर बावजी के पाठ स्थान जहां तप किया कृष्णगंज स्थित वास्थान महादेव मंदिर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया जिसमें जिसमें हजारों भक्तों ने ब्रह्मलीन सद्गुरु देव के मंदिर में पुजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की!

अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट

ललित गर्ग

अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते है लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई है और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरीपेशा का थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन, क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी के नये भारत-सशक्त भारत-विकसित पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं -खेती में उत्पादकता और मजबूती बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन का समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफै रिंग और सर्विसेज, अर्बन डेलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्र र, इन्नोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगा। बजट में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफ दिखाई दी है। विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट प्रस्तुत कर वित्तमंत्री सीमारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से

बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की घोषणा की। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद इस बजट प्रावधानों के माध्यम से देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट ने अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा के साथ राहत की सांसें दी है तो नया भारत- सशक्त भारत-विकसित के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, आदिवासियों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गयी है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनि त नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। विशेषतः नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है।

संभवतः इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक-कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां हर हाथ को काम का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत यह बजट नि त ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षों के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है। बीते कुछ सालों में नरेन्द्र मोदी ने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। बजट में टूरिज्म पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है।. भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। सरकार ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगी, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों, आदिवासियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र एवं पर्यटन पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते है लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई है और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

संपादकीय

केदारनाथ में हादसा

ऊत्तराखंड़ स्थित केदारनाथ में गौरीकुंड के पास पहाड़ी से पत्थर नीचे गिरने के कारण तीन लोगों की मौत वाकई दुखद है। हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। दरअसल, पहाड़ों में बारिशों के कारण अक्सर ही जमीन खिसकने (लैंड स्लाइड) के मामले होते रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लैंड स्लाइड होने के कारण ही यह हादसा हुआ है। हादसा रविवार सुबह हुआ। पहाड़ से बड़े-बड़े. पत्थर गिरने की घटना तीन स्थानों पर हुई। गौर करने वाली बात यह है कि गौरीकुंड-जहां हादसा हुआ है-वहां से केदारनदाथ धाम तक 16 किलोमीटर लंबे पैदल यात्रा मार्ग पर कई संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां हल्की बारिश में ही पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने लगता है। यह पूरा स्ट्रेच भूस्खलन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। इस मामले में कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन भारी बारिश हो रही थी और श्रद्धालु यात्रा पर थे। उन्हें इस आशंका का भान ही न हो सका। यहां प्रशासन की जिम्मेदारी को परखना जरूरी बन जाता है। जब यह बात वहां के प्रशासन और आपदा प्रबंधन को मालूम था तो फिर यात्रियों को इसकी जानकारी देना उनका फर्ज था। वैसे भी केदारनाथ में इससे पहले कई हादसे हुए हैं। बीते आठ वर्षों में वषार्काल के दौरान इस मार्ग पर हादसे में 19 व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ी। इस नाते वहां के प्रशासन को इसकी तैयारियां चौकस रखनी चाहिए थी। यह घनघोर लापरवाही का मामला है। इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि अब प्रशासन अपनी साख बचाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, मगर यह सब कवायद यात्रा शुरू होने से पहले होनी चाहिए थी। ताजा निर्देश के मुताबिक शाम 5 बजे से दूसरे दिन सूर्योदय तक केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यात्रियों की भी जिम्मदारी है कि वो खुद से खतरा मोल न लें। अगर मौसम साफ है और यात्रा में कोई व्यवधान की अग्रिम सूचना नहीं है तभी आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति से लड़कर कोई आज तक जीत नहीं सका है। सभी लोगों को उसके रौद्र रूप की वजहों की तलाश करनी होगी और उसका सम्मान भी करना होगा। पहाड़ी राज्यों में लोगों की जरूरत से ज्यादा आवाजाही और अंधाधुंध निर्माण के कार्यों पर बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना होगा। प्रकृति के साथ तारतम्य बनाने और उसके अनुरूप चलने से ही जान-माल के नुकसान से बचा जा सकता है। यह बात हर किसी को अपने जेहर में रखनी होगी।

चिंतन-मनन

उपाय भी ठीक से हो

एक सास ने बहू से कहा, बहूरानी! मैं अभी बाहर जा रही हूं। एक बात का ध्यान रहे, घर में अंधेरा न घुसने पाए। बहू बहुत भोली थी। सास चली गई, सांझ होने को आई। उसने सोचा कि अंधेरा कहीं घुस न जाए, सारे दरवाजे बंद कर दिए। सब खिड़कियां बंद कर दीं। दरवाजे के पास लाठी लेकर बैठ गई। सोचा- दरवाजा खुला नहीं है, कोई खिड़की खुली है, कहीं भी कोई छेद नहीं। आएगा तो दरवाजा खटखटाएगा, लाठी लिए बैठी हूं, देखती हूं कैसे अन्दर आएगा। पूरी व्यवस्था कर दी। अंधेरा गहराने लगा। सोचा, कहां से आ गया! कहीं भी तो कोई रास्ता नहीं है। हो न हो दरवाजे से ही आ रहा है। अन्धकार को पीटना शुरू कर दिया। काफी पीटा कि निकल जाओ मेरे घर से! मेरी सास की मनाही है कि तुम्हें भीतर घुसना नहीं है! खूब लाठियां बजाई। लाठी टूटने लगी। हाथ छिल गए। लहूलुहान हो गए। अंधेरा तो नहीं गया। परेशान हो गई।

सास आई। दरवाजा खोला। कहा, यह क्या किया? मैंने कहा था कि अंधेरे को मत आने देना घर में। वह बोली, देखो, मेरे हाथ देख लो। लहूलुहान हो गए। लाठी टूट गई। मैंने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर इतना जिद्दी है कि माना ही नहीं और यह तो घुस ही गया। सास ने सिर पर हाथ रखा। कहा, बहूरानी! अंधेरे को ऐसे मिटाया जाता है? क्या अंधेरा ऐसे मिटता है? समझी नहीं तुम बात को। सास ने दीया जलाया, अंधेरा समाप्त हो गया। उपाय के बारे में हमारी जानकारी सही नहीं होती तो हम प्रयत्न तो करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर अंधेरा मिटता नहीं।

...और अब नाम-पहचान पर धर्मयुद्ध?

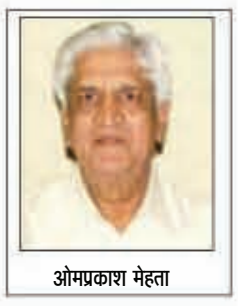

ओमप्रकाश मेहता

आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व एक दमघोटू माहौल में जीनें को मजबूर है, साम्प्रदायिकता का यह जहरीला धुंआ हर किसी के दिल-दिमाग में घुटन पैदा कर रहा है, भारत का 'हिन्दूराष्ट्र' का नारा अब विश्वमंच से लगाया जाने लगा है, इस कारण से एक सम्प्रदाय विशेष में डर तथा चिंता व्याप्त हो गई है, अब यह माहौल क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन सी शक्तियां है? इसका उत्तर तो बाद में खोज लिया जाएगा, किंतु प्राथमिकता इस माहौल को खत्म करने की है, क्योंकि यह माहौल यदि खतरे की सीढ़ी पार कर गया तो पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ सकती है। भारत में इस माहौल की शुरूआत देश को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले उत्तरप्रदेश से हुई है, जहां सबसे पहले धार्मिक रैलियों के मार्ग की दुकानों के बाहर उनके मालिकों के नाम की पि यां लगाने के आदेश प्रदान किए गए, जिसका सबसे पहले अनुसरण पड़ौसी राज्य उत्तराखण्ड़ ने किया जहां कांवड मार्ग की दुकानों पर इस विवादित नियम को लेकर सख्ती बरती गई। उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड के बाद अब छूत का यह रोग मध्यप्रदेश में भी प्रवेश कर गया है और मध्यप्रदेश स्थित देश की सबसे पूण्य व पवित्र नगरी अवंतिका (उज्जैन) में इस नियम को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए। अब आज देश की सबसे बड़ी और अहम् चिंता यही है कि आखिर इन आदेशों को पालन करवा कर देश-प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है? प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पद ग्रहण करते ही आज से एक दशक पहले प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के 'पंचशील' सिद्धांतों की तो इतिश्री कर ही दी थी, जिनमें भारत में शांति की पहल की गई थी, अब आज के शासक देश को साम्प्रदायिक भा ि में झोंक कर अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते है, यदि मोदी जी को अपने तीसरें कार्यकाल में 'हिन्दूराष्ट्र' का संकल्प पूरा करना ही है तो उसके और भी अन्य रास्ते हो सकते है इसके लिए एक सम्प्रदाय विशेष को लक्ष्य बनाने की क्या जरूरत है?

....और अब तो यह मुहीम भारत तक सीमित न रहकर धीरे-धीरे विश्व स्तरीय स्वरूप ग्रहण करती जा रही है, यही आज की चिंता का सबसे बड़ा कारण है यदि देश-विदेश में यही माहौल बना रहा तो इसके परिणाम कितने खतरनाक होगें? इसकी किसी ने कल्पना भी की है? हमारा इतिहास ऐसी मुहीम के परिणामों का गवाह है, इससे आज शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। हमारा पुरातन काल से नारा 'सर्वधर्म समभाव' रहा है, हम आखिर उसे त्यागने को क्यों आतुर है?

शायद इसका मुख्य कारण आज का बदला हुआ माहौल है, हमारा देश हमेशा से धर्मपरायण रहा है, इसीलिए ऋषि-मुनियों ने अपना दबदबा कायम रखा, किंतु अब माहौल एकदम उलट गया है, आज देश के कर्णधार राजनेता साधु-महात्माओं की शरण में नही बल्कि साधु- महात्मा राजनेता की शरण में नजर आ रहे है, अब ऐसे में सहज ही देश, प्रजा और यहां के आध्यात्म के भविष्य की कल्पना की जा सकती है।

वैसे इस स्थिति के लिए कोई दोषी नही है, न राजनेता और न उनके आराध्य। दोषी है तो कुर्सी का मोह, जिसने एक बार कुर्सी प्राप्त कर ली वह उसे 'दीर्घजीवी' बनाने की कौशिश करता है और यही भावना आज की राजनीति का मुख्य केन्द्र है, अब ऐसे में यह सवाल पैदा होना स्वाभाविक है कि इसका ईलाज क्या है? तो सत्य बात यह है कि इसका ईलाज किसी संत-मौलवी या डॉक्टर के पास नही बल्कि स्वयं

रोगी के पास है, जो अपने में आत्म चेतन पैदा कर अपने आपको ठीक कर सकता है और वही अब करना भी चाहिए, दुकानों पर नाम प ि लगाने से कुछ नही होगा।

पाकिस्तानः पूर्व सैनिक बनाए जा रहे आतंकवादी

प्रमोद भार्गव

पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर में आतंकवादी हमले तेज कर दिए हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद घाटी के हालात में जबरदस्त सुधार देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। स्थानीय स्तर पर घाटी के मुस्लिम युवाओं ने आतंक की राह छोड़कर जब करियर बनाने की दिशा में पहल कर दी तो पाक की भारतीय सीमा में युवाओं को लालच देकर आतंकी बनाने की मंशा पर विराम लग गया।

अतएव अब उसने अपने ही पूर्व सैनिकों को प्रलोभन देकर आतंकी बनाकर घुसपैठ करानी शुरू कर दी। नतीजतन भारतीय जमीन पर एक बार फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला तेज हो गया। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सेना के कप्तान समेत पांच जवान शहीद हो गए। सुरक्षाबल निरंतर आतंकियों को मार गिरा रहा है। बावजूद घुसपैठ का सिलसिला बना हुआ है, जो देश और सेना के लिए चिंता का सबब है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक घाटी में करीब डेढ़ माह से जारी आतंकी हमलों में पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिकों की लिप्ता के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। एजेंसियां इसका यह भी मानकर चल रही हैं कि घाटी में भारी मतदान के बाद पाकिस्तान हताशा के दौर से गुजर रहा है। उसे आशंका है कि कहीं विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर प्रांत में लोकतंत्र की बहाली न हो जाए? इसलिए वह घाटी में हमलों के जरिए माहौल खराब करके दहशत का वातावरण रचने में लगा है। अलगाववादी सुर का आलाप करने वाले मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार को मतदाता ने हराकर यह साबित कर दिया कि घाटी के हालात बदतर करने में इन परिवारों की भूमिका अहम रही है। इससे पाक ने शायद अंदाजा लगाया है कि विधानसभा चुनाव के बाद घाटी में जो प्रजातांत्रिक सरकार बनेगी, वह पाक की मंशा के अनुरूप चलने वाली नहीं है। इसलिए माहौल खराब करके चुनाव को टला जाए। इस बीच पाकिस्तान की फंडिंग से घाटी की तरह जम्मू क्षेत्र में आतंकियों की मदद करने वाले ओवर ग्राउंड कार्यकताओं का एक नेटवर्क भी तैयार किया है। इसे सेना ध्वस्त करने में लगी है। डोडा किश्तवार, पुंछ, राजौरी, रियासी और कठुआ के कठिन भौगोलिक इलाकों में पिछले दो दषक में जैश-ए-मोहम्मद और लश्करे तैयबा ने ओवर ग्राउंड वार्कर नेटवर्क खड़ा किया था। यह अंततरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से आने वाले आतंकियों को घाटी के सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम करता था। घाटी में रहने वाले ये वार्कर घने वनों और दुर्गम इलाकों में छोटे-छोटे घर बनाकर रह रहे हैं। रियासी जिले में हिंदू भक्तों की बस पर गोली चलाने वाले आतंकियों को इन्हीं ओवर ग्राउंड वर्कर ने मदद की थी। भारतीय सेना के अनुसार ओवर ग्राउंड वार्का वे लोग होते हैं, जो उग्रवादी या आतंकवादियों को रसद, नकदी, आश्रय और अन्य रहने लायक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सेना इस नेटवर्क को नष्ट कर रही है। पाक सेना कितनी दगाबाज है, इसका खुलासा पाक के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एवं पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व अधिकारी शाहिद अजीज ने द नेशनल डेली' में किया था। इसमें कहा गया था कि कारगिल युद्ध में पाक आतंकवादी नहीं, बल्कि उनकी वर्दी में पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक ही लड़ रहे थे और इस लड़ाई का लक्ष्य सियाचिन पर कब्जा करना था। चूंकि यह लड़ाई बिना किसी योजना और अंतरराष्ट्रीय हालात का अंदाजा लगाए बिना लड़ी गई थी, इसलिए तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पूरे मामले को रफा-दफा कर दिया था। इससे यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि पाकिस्तानी फौज इस्लामाबाद के पूरे नियंत्रण में नहीं है। आतंकी सरगना हाफिज सईद भारत-पाक सीमा पर खुलेआम घूम रहा है। जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी दहशतगर्दी फैलाने में शरीक हैं।'

पाकिस्तान पूर्व सैनिकों को आतंकी बना रहा है। इसका सत्यापन इस तथ्य से भी होता है कि हाल ही में मारे में जिन आर्तकियों से खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं, उनका संचालन आसानी से सेना से प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। इन हथियारों में एम-4 कार्बाइन, 509 टैक्टिगल गन और एम-1911 और स्टेयर एयूजी रायफल बरामद हुई हैं। आर्तकियों के पास से अल्ट्रा और माइक्रो रेडियो सेट भी बरामद हुए हैं। इनके नेटवर्क में सेंध लगाना आसान नहीं है। ये उपकरण भी अमेरिका द्वारा निर्मित हैं। अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया था। अतएव ऐसी आशंका है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा छोड़े गए हथियार अब जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आर्तकियों तक पहुंच रहे हैं। यदि यह तथ्य एक ठोस सच्चाई है तो कश्मीर में आतंकी हिंसा का दु क्र बढ़ता दिखाई दे सकता है? दरअसल, ये हथियार पाकिस्तान के जरिए भी आर्तकियों को मिल सकते है और सीधे अफगानिस्तान से भी लाए जा सकते हैं। भारतीय एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं, कि इन्हें तालिबान सीधे आर्तकियों को आर्थिक बदहाली दूर करने के लिए बेच भी रहा है। पिछले चार वर्ष से आर्तकियों के पास स्टेयर एयूजी रायफल होने के सूचनाएं मिल रही थीं।

सहायक अभियंता विद्युत वितरण कार्यालय परिसर आसींद में भारतीय मजदूर संघ का 70 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया

द पुलिस पोस्ट

सांवर मल शर्मा आसींद कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता व संस्थापक दत्तोपंत ठेगड़ी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन तथा संगठन गीत के साथ शुरू हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, मुख्य वक्ता शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रांत सह संगठन मंत्री पोखर लाल गुर्जर, अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी सदस्य जमनालाल रैगर, स्थानीय कार्यालय के सहायक अभियंता नरेश मीणा थे। भारतीय मजदूर संघ के स्थानीय इकाई अध्यक्ष देवीलाल शर्मा ने अतिथियों सहित सभी आगंतुक सदस्यों का स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने विचार व्यक्त करते हुए भारतीय मजदूर संघ के सभी सदस्यों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी एवं परिवार जनों के स्वास्थ्य, शिक्षा, संपन्न व खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्य वक्ता प्रांत सहसंगठन मंत्री पोखर लाल गुर्जर ने उद्बोधन देते हुए बताया कि भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेगड़ी के सनातन आधारित संघ प्रचारक जीवन, संगठन कुशलता, कार्य के प्रति अक्षेय निष्ठ होकर विभिन्न विचारधाराओं के मजदूर संघों का गहन अध्ययन उनके बीच रहकर ही नहीं उनके प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के पदों को प्रत्यक्ष धारण कर अनुभव किया कि सारे मजदूर संघ किसी न किसी राजनीतिक दल की मजदूर इकाई के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रव्यापी अध्ययन के बाद 69 वर्षों पूर्व 23 जुलाई 1955 को भोपाल में अनान्य प्रान्तों के 35 प्रतिनिधियों के साथ किसी भी राजनीतिक दल की मजदूर इकाई बने बिना, स्वतंत्र व मजदूरों के हित में संगठन के रूप में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना त्रिसूत्रों के साथ की। देशहित में औद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। संगठन का सिद्धांत है सामूहिक चर्चा, सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व। इसी संगठन कुशलता के आधार पर तथा दूसरों की लकीर को बीना मिटाये अपनी लकीर लम्बी खींचने की सकारात्मक सोच रखने वाले कार्यकर्ताओं के दम पर लगभग दो करोड़ सदस्य संख्या के साथ आज संसार का सबसे बड़ा मजदूर संघ है। पूर्ण अनुशासन के साथ उचित मांगे, उचित तरीके से, उचित स्थान पर पहुंचाते हैं। तथा संगठन का नारा है राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। जबकि अन्य संगठनों का नारा होता है। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। राष्ट्र प्रथम का व्रत लेकर के सभी सदस्य राष्ट्र हित में अपना काम करते हैं। काम का पूरा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। सहायक अभियंता नरेश मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। भारतीय मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी सदस्य जमनालाल रैगर ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया तथा सभी का आभार व्यक्त किया।कार्यक्रम का संचालन विनोद जोशी ने किया। प्रहलाद ,धीरज कुमार, भैरुसिंह राठौड़,मुरली लोहार, विष्णु, प्रकाश, दिनेश, रत्नेश आदि उपस्थित रहे।राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई।

सामाजिक सरोकार के तहत स्वाभिमान जल कार्यक्रम पर विजिट का आयोजन स्कूल की छात्र–छात्राओं ने किया अवलोकन

द पुलिस पोस्ट

सामाजिक सरोकार के तहत जवाहर फाउंडेशन द्वारा स्वाभिमान जल के कार्यक्रम के अंर्तगत बनेड़ा के ग्रामीण समुदाय को शुद्ध एवम स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा रहा है स्वाभिमान जल कार्यक्रम को जागरूक करने के लिए स्थानीय विद्यालय अचीवर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेड़ा के विद्यार्थियों के समाज उपयोगी विषय हेतु स्वाभिमान जल वाटर एटीएम पर विजिट की गई इस दौरान विद्यार्थियों ने वाटर एटीएम के स्मार्ट कार्ड युक्त आरओ प्लांट की कार्यप्रणाली के बारे में समझाइश की गई एवम शुद्ध एवम स्वच्छ जल अति आवश्यक है इसके बारे में जागरूक किया गया व ग्राम वासियों का दुषित जल पीने से होने वाली बीमारियां के कारण अत्यधिक स्वास्थ्य एवं आर्थिक नुकसान होता है इस विषय से अवगत कराया इनसे होने वाली नुकसान और बीमारियों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया इस दौरान सभी विद्यार्थियों को स्वाभिमान जल के प्रचार प्रसार करने हेतु पंपलेट भी वितरण किए गए। जवाहर फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमुख उद्योगपति श्री रिजु झुनझुनवाला की एक सामाजिक सरोकार के तहत पहल है जिसमें स्वाभिमान भोज (एक रुपए में भोजन)' स्वाभिमान जल(स्वच्छ एवं शीतल पेयजल)) तथा स्वाभिमान शिक्षा(मुफ्त डिजिटल लिटरेसी) तीनों कार्यक्रम वृहद रूप से संचालित है और आम जनों को इसका लाभ मिल रहा है इस दौरान विद्यालय के शिक्षक एवम जवाहर फाउंडेशन के लोकेंद्र पंड्या एवम चिराग टेलर मौजूद रहे

बिजली के पोल पर आधा घंटे तक लटका रहा लाइनमैन:करंट के बाद लगी आग, एक पैर कटकर हुआ अलग; क्रेन से उतारी डेडबॉडी

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा। बिजली के पोल पर लाइन को ठीक कर रहे ठेकाकर्मी लाइनमैन की करंट से मौत हो गई। युवक का एक पैर कटकर अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। आधे घंटे तक युवक का शव तारों पर लटका रहा। मामला भीलवाड़ा के प्रतापनगर इलाके का मंगलवार सुबह 11 बजे का है। एएसआई चिराग अली कायमखानी ने बताया- मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला सौरभ पटेल (22) भीलवाड़ा में बिजली विभाग में ठेकेदार के पास लाइनमैन था। मंगलवार को सौरभ बापूनगर इलाके की हेमू कॉलोनी पार्क के पास ट्रैक्टर क्रेन पर चढ़कर बिजली लाइन पर काम कर रहा था। इसी दौरान बिजली सप्लाई चालू होने से करंट दौड़ गया। सौरभ पोल और लाइन से चिपक गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौकै पर लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे का पता चलते ही कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई बंद की। प्रतापनगर पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पहुंचे। दोपहर 12 बजे लाइनमैन का शव क्रेन की मदद नीचे उतरा गया। पोस्टमॉर्टम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिजवाया। जानकारी के अनुसार सौरभ 4 दिन पहले ही भीलवाड़ा आया था। वह परिचित के पास ठहरा था। उसका परिवार सागर में ही रहता है। ठेकेदार ने कर्मचारी को सौरभ के गांव भेजा है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। मामले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वीके संचेती को दो बार कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया।

न्यायालय ने सरपंच एवं प्रधान पति के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज करने के दिए आदेश

द पुलिस पोस्ट

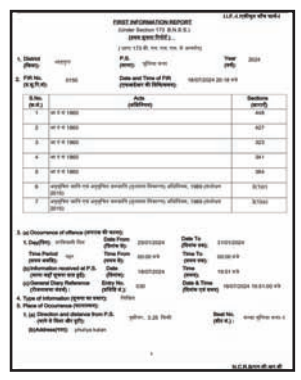

भीलवाड़ा / स्थानीय एससी, एसटी प्रकरण न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने अपने प्रकरण संख्या 8/ 2024 की सुनवाई करते हुए शाहपुरा जिले के फुलिया कलां निवासी एवं हाल ग्राम पंचायत सणगारी के सरपंच भागचंद चढ़ा तथा शाहपुरा पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती माया देवी जाट के पति धर्मराज जाट के विरुद्ध एससी, एसटी एक्ट की धारा में एफ आई आर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश प्रदान किए हैं । कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष एवं पीड़ित रामदयाल पिता नारायण लाल बलाई निवासी फुलिया कलां (शाहपुरा) ने एससी, एसटी एक्ट प्रकरण न्यायालय भीलवाड़ा में धारा 156 (3) जाप्ता फौजदारी के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोप लगाया कि तबीजी (अजमेर) निवासी हाल मुकाम थाना फुलिया कलां शाहपुरा के प्रकाश चौधरी, हीरालाल गोदारा तथा सणगारी सरपंच भागचंद जाट, धर्मराज जाट निवासी ग्राम पंचायत सणगारी ने हम सलाह होकर प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5549/3296 एवं आराजी नंबर 5551/3298 के प्लॉट संख्या 13 की साइज 19 बाई 40 फीट पर पर दो-दो फीट नींव खोदकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थी जब अतिक्रमी प्रकाश चौधरी के पास गया तो वहां भागचंद चढ़ा, धर्मराज जाट तथा हीरालाल गोदारा ने प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जातिगत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी, और चारों व्यक्तियों ने कहा कि यहां तुम्हारा कोई प्लॉट नहीं है दोबारा नजर आए तो अच्छा नहीं होगा, जबकि प्रार्थी ने अपने प्लॉट पर निजी संपत्ति होने का बोर्ड भी लगा रखा था जिसको भी अभियुक्त गण उखाड़ कर ले गए। पीड़ित बलाई ने अदालत को बताया कि यह लोग प्रॉपर्टी दलाल हैं और आए दिन कमजोर वर्ग से जुड़े एसी एसटी वर्ग के लोगों के साथ गाली गलौच कर लड़ाई झगड़ा कर उन्हें डराते धमकाते हैं और उनकी संपत्ति पर कब्जा करते हैं पूर्व में भी एसी वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास में जेल जा चुके हैं । प्रार्थी ने 31 जनवरी 2024 को थाना फुलिया कला पर रिपोर्ट पेश की लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, पीड़ित पक्ष ने पुनः 20 फरवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक शाहपुरा के समक्ष भी न्याय की गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया मजबूर होकर प्रार्थी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा जहां अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना फुलिया कलां को अपराध धारा 448 427 323 341 384 आईपीसी सहित 3 (1) (फ) (र) एसी एसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर डीवाईएसपी रमेश तिवारी शाहपुरा को अनुसंधान कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश प्रदान किये है। वृताधिकारी (Dysp) ने गत गुरुवार को प्रकरण संख्या 150/24 दर्ज कर जांच प्रारंभ की है

दो बसों की टक्कर में 2 की मौत, 12 घायल:एक व्यक्ति बस के नीचे दबा, क्रेन की मदद से बस को उठाकर निकाला शव

द पुलिस पोस्ट

बारां। ओवरब्रिज पर सड़क पर बैठी गायों को बचाने के लिए बस ने जैसी ही लाइन चेंज की पीछे आ रही तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इससे आगे चल रही बस पलट गई। हादसे में दो लोगों की मौत और 12 से अधिक घायल हो गए। इनमें 8 लोगों की हालत गंभीर है। बस पलटने से एक व्यक्ति उसके नीचे दब गया। क्रेन की मदद से बस को उठाकर नीचे दबे व्यक्ति के शव को निकाल गया। हादसा मंगलवार सुबह 11 बजे नेशनल हाईवे-27 पर बारां में आमापुरा ओवरब्रिज पर हुआ। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि ओवरब्रिज पर सड़क पर बैठी गायों को बचाने के कारण आगे चल रही बस ने अपनी लाइन चेंज की। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने आगे चल रही बस को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद आगे चल रही बस पलट गई। हादसे में चजवा निवासी मुकेश प्रजापति (34) और टोंक निवासी नरेश (30) की मौत हो गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए। 8 लोगों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक घंटे बंद रहा मार्ग

एसपी ने बताया कि मौके पर चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग ओवरब्रिज पर पहुंचे और घायलों को बस से निकाला। सड़क हादसे की सूचना लगते ही जिला कलेक्टर तुरंत मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से बस को ऊंचा कर बस के अंदर फंसे एक व्यक्ति के शव को निकल गया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक मार्ग पूरी तरह बंद रहा।

एक गोवंश की मौत

एसपी ने बताया कि आगे चल रही बस छबड़ा से बारां बस स्टैंड जा रही थी। उसके पीछे चल रही बस नाहरगढ़ से बारां बस स्टैंड के लिए ही जा रही थी।

ये हुए घायल

अस्पताल चौकी कॉन्स्टेबल कलवाराम ने बताया कि हादसे में मुंडला निवासी दिनेश, कुंडी सकरावदा निवासी कैलाश बाई, अटरू निवासी सुरेंद्र सिंह, अहमदी निवासी नितेश, बाबूलाल, बजरंग गढ़ निवासी गुड्डी बाई, नंदकिशोर, जगन्ननाथी बाई गंभीर घायल हुए हैं।

पशुओं को हटाने के लिए सख्ती से करेंगे कार्रवाई

जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने घटना पर गंभीरता जताते हुए कहा कि सड़क से आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाल ही में एनएचएआई और संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए थे। पशुओं को हटाने के लिए अब सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी और आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाया जाएगा। फिलहाल हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नेमप्लेट हटाने से डर रहे कारोबारी

मुजफ्फरनगर ।उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर होटल से लेकर ठेले वालों के लिए नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम आदेश के बावजूद अभी दुकानदार नेमप्लेट हटाने से डर रहे हैं। इसके लिए अभी भी प्रशासन की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। मुजफ्फरनगर के दुकानदार ने बताया कि वे अभी नेमप्लेट हटाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक अन्य दुकानदार ने कहा कि दस दिन पहले तक हर रोज का खर्च 15 हजार रुपये था। लेकिन पिछले 24 घंटे में केवल 4 हजार की कमाई हुई है। हालांकि चाय और खाने में पूरी सतर्कता बरतते हैं, लेकिन लोग नाम पढ़कर ही आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये बोर्ड परमानेंट के लिए हटने चाहिए। इससे दुकानदारी घट गई थी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। हां जी हमने बोर्ड हटा दिए हैं, देखिए यह भेदभाव था यह बोर्ड परमानेंट हटने चाहिए। इससे कारोबार पर बहुत गलत असर पड़ रहा था, जिससे दुकानदारी घट गई थी।

चेन्नई एयरपोर्ट पर .... जब मधुमक्खियों ने फ्लाइट को घेरा

रायपुर ।चेन्नई एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब घटना हुई, यहां रायपुर जा रही एक फ्लाइट पर मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया। हजारों मधुमक्खियों ने प्लेन को घेर लिया, इससे उड़ान में दो घंटे की देरी हुई। फ्लाइट में छत्तीसगढ़ भाजपा नेता मितुल कोठारी सहित 150 यात्री सवार थे। मधुमक्खियों की संख्या इतनी थी कि यात्री डर से फ्लाइट में सवार होने के लिए बस से उतर नहीं सके। घटना तब हुई जब यात्रियों को बस से प्लेन तक ले जाया जा रहा था। तभी अचानक, बड़ी संख्या में मधुमक्खियां दिखाई दीं और उन्होंने पूरे प्लेन को घेर लिया। ग्राउंड स्टाफ ने खुद को प्लास्टिक के कवर से ढककर मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियां प्लेन के इंजन के पास जमा होने लगीं। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। धीरे-धीरे मधुमक्खियों की संख्या कम हुई और यात्रियों को सुरक्षित रूप से प्लेन में चढ़ाया गया। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंजन में कोई मधुमक्खी न फंसी हो, फ्लाइट इंजीनियर्स ने प्लेन की पूरी जांच की। इसके बाद ही प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति मिली। इस घटना के बारे में भाजपा नेता कोठारी ने कहा कि जब हम बोर्डिंग के लिए बस में सवार हुए, तभी हमें बड़ी संख्या में मधुमक्खियां दिखाई दीं। उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टाफ ने प्लास्टिक के कवर से खुद को ढक लिया और मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियां प्लेन के इंजन के पास जमा हो गई थीं, जिसके बाद स्टाफ ने केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करके उन्हें हटाया।

बीआरएस नेता कविता 26 जुलाई को कोर्ट में होंगी पेश, राउज़ एवेन्यू ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कविता को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें सीबीआई ने इस साल जून में आरोप पत्र दाखिल किया था और दावा किया था कि मामले में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सारे सबूत मौजूद हैं। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। कोर्ट ने सीबीआई मामले में आरोपी कविता और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले, ईडी ने भी बीआरएस नेता कविता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने दावा किया था कि कविता ने तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आप नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुचित लाभ लेने की साजिश रची थी। दिल्ली की शराब नीति को अब खत्म कर दिया गया है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने साजिश और इंडो स्पिरिट्स के गठन के जरिए 292.8 करोड़ रुपए की अपराध आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया, जो साजिश और रिश्वत के भुगतान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई थी। बता दें कि के. कविता को लेकर ईडी का दावा था कि आप नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता, इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थीं. इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इस साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।

भारी बारिश... एन-1 बी डेम क्षतिग्रस्त

दंतेवाड़ा ।छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम मेहरबान राज्य के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। बस्तर इलाके में भीषण बारिश से आसपास के जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं। दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल पहाड़ी में एनएमडीसी द्वारा निर्मित एन-1 बी डेम क्षतिग्रस्त हुआ है। जिला प्रशासन ने बताया कि अत्याधिक बारिश के कारण डेम क्षतिग्रस्त हुआ है। इसकारण अनेक घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा किरंदुल के गाटर पुलिया एवं सीएससी सेंटर के पास भी बारिश से जल जमाव हो गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन मौके पर तैनात होकर रेस्क्यू कर रहा है तथा प्रभावित परिवारों को मंगल भवन में ठहराया जा रहा है। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के समीप रहने वाले लोगों को अन्य जगह शिफ्ट होने की हिदायत दी जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नया मानसूनी सिस्टम पूरे प्रदेश में सक्रिय है जिस कारण से तेज बारिश हो रही है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून से अब तक राज्य में 355.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी के घर तक लेटकर क्यों पहुंचा सरपंच

महासमुंद (ईएमएस)। छत्तीसगढ़ के एक सरपंच ने दिल्ली में अनोखा प्रदर्शन किया है। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास मांग लेकर एक सरपंच सड़क पर लेटते हुए उनके आवास तक पहुंचा। सरपंच की मांग है कि उसके गांव में सड़क नहीं है। इसलिए वे गांव में सड़क निर्माण के लिए केन्द्रीय मंत्री के पास पहुंचा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ग्राम पंचायत बंबूरडीह के सरपंच शत्रुघ्न चेलक हैं। सरपंच अपने गांव में सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। बताया जाता है कि गांव के लोगों ने चंदा करके सरपंच को पांच हजार रुपये दिए। सरपंच इन पैसों से दिल्ली पहुंचा और सड़क की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। हालांकि सरपंच से गडकरी की मुलाकात नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, गड़करी उस समय अपने आवास पर नहीं थे। सरपंच चेलक ने बताया कि वह दो किमी की सड़क बनवाने के लिए नेता और अधिकारियों की चक्कर लगाते-लगाते थक चुके हैं। कहीं से भी उन्हें सड़क बनाने का भरोसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सड़क रामाडबरी से बावनकेरा गांव तक बननी है। अभी कच्ची सड़क है। बारिश के सीजन में सड़क पर चलना मुश्किल होता है। सरपंच ने बताया कि गांव में सड़क नहीं होने से लोग गांव में शादी करने नहीं आते हैं। लड़के-लड़कियों की शादी सड़क के कारण नहीं हो पाती है। ग्रामीण भी लगातार इस सड़क के लिए मंत्री और नेताओं से मिलते हैं लेकिन अभी तक सड़क बनाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। सरपंच ने बताया कि इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे गांव का नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ही नहीं है।

नौसेना प्रमुख ने दी रक्षा मंत्री को युद्धपोत में हुए नुकसान की जानकारी

नई दिल्ली। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने से हुए नुकसान की जानकारी दी है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में सोमवार को आग लग गई थी। इस हादसे में युद्धपोत को काफी नुकसान हुआ है। नौसेना के मुताबिक बाद में यह युद्धपोत एक तरफ झुक गया और कोशिशों के बावजूद इसे सीधा नहीं किया जा सका। एडमिरल त्रिपाठी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को सोमवार शाम को ही इस हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। नौसेना प्रमुख स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को मुंबई पहुंचे।

बिना मुस्लिमों के नहीं हो सकती अमरनाथ-वैष्णो देवी यात्रा, कांवड़ यात्रा वाले फरमान पर उमर अब्दुल्ला का आया ये बयान

श्रीनगर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार के विवादास्पद कांवर यात्रा आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को जानना चाहा कि क्या अमरनाथ और वैष्णो देवी तीर्थयात्रा भी मुसलमानों के बिना संभव होगी। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि अगर (कांवड़ यात्रा) आदेश का मकसद मुसलमानों को दूर रखना है, तो भगवान के लिए, मुझे बताएं, जब (अमरनाथ) यात्रा यहां (जम्मू-कश्मीर) होती है...तो यह मुसलमानों के बिना संभव नहीं है। अपनी बात को विस्तार से बताते हुए उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का उदाहरण भी दिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि अमरनाथ यात्री मुसलमानों के कंधों पर यात्रा करते हैं। जो लोग माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों को घोड़ों या पिठुओं (कुली) पर ले जाते हैं...वे किस धर्म के हैं? वहां, भाजपा धर्म नहीं देखती है। अब्दुल्ला की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई तक भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के व्यापक आलोचना वाले आदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जारी किए गए इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगाने के एक दिन बाद आई है। पार्टी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों पर शासन करती है। इसके निर्देश की भाजपा सहयोगियों ने भी आलोचना की, उत्तर प्रदेश ने वार्षिक कंवर तीर्थयात्रा के मार्गों पर भोजनालयों और खाद्य स्टालों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया; विपक्ष ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी मुस्लिम समुदाय का 'आर्थिक बहिष्कार' करने की कोशिश कर रही है।

सावन के पहले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने लाखों कांवड़ियों को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। योगी का ये फैसला इसलिए आया था क्योंकि कई दुकान, ढाबे और होटल मिले जिनके नाम तो हिंदू थे लेकिन मालिक मुसलमान। ऐसे में सीएम योगी ने आदेश दिया कि सही नाम के साथ ही दुकान चलानी होगी। इस सख्ती के बाद कई दुकानों ने अपने असली नाम लगाए। योगी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो गए, बुद्धिजीवि बौखला गए। योगी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों सिर्फ खाने का प्रकार बताने की जरूरत है।

कफ सिरप को लेकर शक निकला सही....क्लालिटी टेस्ट में फेल

नई दिल्ली। कफ सिरप को लेकर भारत की फार्मा कंपनियों पर दुनिया के कई देशों में सवाल उठने के बाद सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 100 कफ सिरप क्लालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गांबिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार खांसी की सिरप में जो टॉक्सिन मौजूद थी वहीं टॉक्सिन इन सिरप में भी पाया गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्राइकोल पाए जाने की वजह से 100 कंपनियों के कफ सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि डीईजी/ईजी, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, पीएच वॉल्यूम के आधार पर कफ सिरप को एनएसक्यू की श्रेणी में रखा गया है। 7087 बैच दवाओं की जांच की गई जिसमें से 353 को एनएसक्यू की श्रेणी में रखा गया। वहीं 9 सैंपल में डीईजी और ईजी की मात्रा थी। गुणवत्ता ठीक ना होने की वजह में डीईजी और ईजी की उपस्थिति के अलावा असुरक्षित सप्लाई चेन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल बल्क टेस्टिंग में फेल होने को बताया गया है। कई देशों में बच्चों की मौत के बाद भारत में बनने वाली कफ सिरप पर सवाल खड़े किए गए हैं। इसके बाद सरकारी और प्राइवेट लैब्स में इनकी जांच की जा रही है। डीजीसीई ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलर्स से कहा है कि एक्सपोर्ट के लिए बनाई जा रही कफ सीरप की गंभीरता से जांच की जाए। इसके आलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेड ट्रेड ने भी कफ सिरप के निर्यातकों को निर्देश दिया कि दवा विदेश भेजने से पहले सरकारी लैब में टेस्ट कराए।

'दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, सिर्फ राजनीतिक मिशन है', मोदी सरकार के बजट पर भड़कीं ममता बनर्जी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 को 'राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी' करार दिया और राज्य को 'वंचित' करने के लिए केंद्र की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पश्चिम बंगाल ने क्या गलती की है कि उसे केंद्र द्वारा 'वंचित' किया गया है। बजट को लेकर ममता ने एक बयान में कहा कि यह दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, सिर्फ राजनीतिक मिशन है। मुझे कोई रोशनी नहीं दिखती, अंधेरा है।

ममता ने कहा कि वे चुनाव के दौरान बड़े-बड़े दावे और वादे करते हैं। लेकिन वोट मिलने के बाद वे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लोगों को यह याद रखना चाहिए। सिक्किम को चीजें मिलने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दार्जिलिंग को वंचित रखना ठीक नहीं है। यह बजट जनविरोधी है, गरीब विरोधी है और आम लोगों के लिए नहीं है।' यह एक पार्टी को खुश करने वाला बजट है। यह राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भरा बजट है।

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि मैं इसे छेड़छाड़ वाला बजट कहता हूं...प्रमुख समस्याएं - 9.2प्र. पर बेरोजगारी और 5प्र. पर मुद्रास्फीति - का बिल्कुल भी समाधान नहीं किया गया है। राज्यों को उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को फायदा हुआ। यह बिल्कुल भी अच्छा बजट नहीं है। उन्होंने बुनियादी ढांचे में सब कुछ निवेश किया है, जिसे आकार लेने में काफी समय लगेगा। इसलिए, यह कोई बुद्धिमानी भरा बजट नहीं है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले दस सालों में बजट से आम आदमी, किसानों, छात्रों को क्या मिला?...पहले सिर्फ एक राज्य गुजरात के लिए बजट बनता था, अब इसमें दो राज्य और जुड़ गए हैं...पहली बार ,मैंने देखा है कि देश के कल्याण के लिए नहीं बल्कि सरकार बचाने के लिए बजट बनाया गया है।' विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भाजपा के सहयोगियों और 'क्रोनीज़' को खुश करना है। कांग्रेस नेता ने दस्तावेज़ को 'कुर्सी बचाओ' बजट बताया और आरोप लगाया कि यह कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र से नकल किया गया था।

राहुल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि 'कुर्सी बचाओ' बजट। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''सहयोगियों को खुश करने के लिए अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। अपने मित्रों को खुश किया गया, 'एए' को लाभ दिया गया, लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले कुछ बजट का 'कॉपी-पेस्ट' किया गया है।''

लोकसभा स्पीकर की बेटी अंजलि पहुंची हाईकोर्ट

-झूठे आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया दायर

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईआरपीएस अधिकारी अंजलि बिरला ने झूठे आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अंजलि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी हैं। वह सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने की मांग कर रही हैं जिनमें उन पर झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने (अंजलि) अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अपने मानहानि मुकदमे में, अंजलि बिरला ने कहा है कि कई सोशल मीडिया पोस्ट उनके बारे में भ्रामक और झूठी जानकारी फैला रहे हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि ये प्रकृति में मानहानिकारक हैं।

अंजलि ने अपनी याचिका में कहा है कि फैलाए जा रहे झूठे और निराधार आरोप वादी की प्रतिष्ठा को गैरकानूनी रूप से नुकसान पहुंचाने और मानहानिकारक आख्यानों के जरिए से खड़े होने के स्पष्ट इरादों का संकेत देते हैं। अकेले इस दावे के आधार पर, वादी का मानना है कि वर्तमान मुकदमा अपनी योग्यता के आधार पर सफल होना चाहिए। इसके बाद जस्टिस नवीन चावला की बेंच इस मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गई। अंजलि की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव नायर ने मामले को सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।

सूत्रों के मुताबिक मुकदमे में कहा गया है कि कई व्यक्ति बिना किसी सच्चाई या सबूत के वादी की पेशेवर प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के खिलाफ विवाद पैदा करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से वादी को ही निशाना बना रहे हैं। यह मुकदमा प्रतिवादियों को वादी और उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें उनके पिता ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं की भी प्रतिष्ठा को धूमिल करने से रोकने के लिए लाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में अजित गुट के लगाए पोस्टर से मुख्यमंत्री गायब, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं?

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से तनाव के संकेत मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ा गया। इसके बाद अब विधानसभा सीटों के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। अब अजित पवार की एनसीपी की ओर से लड़की-बहिन योजना के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पिछले महीने विधानसभा में अपने बजट भाषण में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना की घोषणा की थी। अजित एकनाथ शिंदे सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। ये पोस्टर सोमवार को अजित पवार के जन्मदिन के अवसर पर अहमदनगर जिले के पारनेर, अहमदनगर, श्रीगोंडा और कर्जत-जामखेड विधानसभा क्षेत्रों के उनके दौरे के पहले लगाए गए थे।

यहां आयोजित कार्यक्रमों में अजित पवार ने महिलाओं को संबोधित कर योजना का उल्लेख 'माझी लाडकी बहिन' के रूप में किया, जबकि 'मुख्यमंत्री' शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया। इस योजना के तहत उन परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम है। डिप्टी सीएम पवार ने बीते महीने बजट के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। अजित इस बीच अहमदनगर, श्रीगोंजा, करजात-जमखेद क्षेत्रों में गए ताकि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बढ़त बनाई जा सके। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और इसी दौरान ये पोस्टर सामने आए। उनके इन दौरों के समय ही पिंक कलर में पोस्टर लगाए गए थे। इनमें अजित पवार की तस्वीरें तो थीं, लेकिन सीएम का जिक्र तक नहीं था।

बजट कागजों पर अच्छा, किसानों को कोई फायदा नहीं: टिकैत

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए और नौ प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की जिसमें उत्पादकता बढ़ाना शामिल है। अपने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने कहा कि अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी।

मोदी सरकार बजट किसान नेता राकेश टिकैत को पसंद नहीं आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र को कागजों पर यह बजट अच्छा लग सकता है लेकिन जमीन पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे उन कंपनियों को फायदा होगा जो किसानों को जैविक खेती सिखाएंगी। उन्होंने मांग की कि सरकार को फसलों की कीमत चुकानी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए था।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले दो सालों में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। पांच राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना एक नीतिगत लक्ष्य होगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहकारी क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के कार्यान्वयन की सुविधा भी देगी। उन्होंने झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देने की घोषणा की।

भारत में 2050 तक 34 करोड़ 60 लाख हो जाएगी बुजुर्गों की संख्या

-महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में अधिक निवेश की जरुरत

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूएनएफपीए-इंडिया की रेजिडेंट प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार ने विश्व जनसंख्या दिवस के कुछ दिनों बाद जनसंख्या के उन प्रमुख रुझानों को रेखांकित किया, जिन्हें भारत सतत विकास में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता दे रहा है।

इनमें युवा आबादी, वृद्ध जनसंख्या, शहरीकरण, प्रवासन और जलवायु के अनुसार बदलाव करना शामिल हैं। ये कारक सभी देश के लिए अनूठी चुनौतियां और अवसर पेश करते हैं। वोजनार ने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 2050 तक दोगुनी होकर 34 करोड़ 60 लाख हो जाने का अनुमान है। देश में खासकर उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है, जिनके अकेले रह जाने और गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है। इसलिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि खासकर वृद्ध महिलाओं के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जिनके अकेले रहने और गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है।

यूएनएफपीए-इंडिया प्रमुख ने कहा कि भारत में युवा आबादी काफी है और 10 से 19 वर्ष की आयु के 25 करोड़ 20 लाख लोग हैं। उन्होंने जिक्र किया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सृजन में निवेश करने से इस जनसांख्यिकीय क्षमता को भुनाया जा सकता है और देश को सतत प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। वोजनार ने कहा कि भारत में 2050 तक 50 प्रतिशत शहरी आबादी होने का अनुमान है, इसलिए झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का निर्माण महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा कि शहरी योजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जरूरतों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा एवं नौकरियों तक पहुंच को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके। वोजनार ने यह भी कहा कि आंतरिक और बाहरी प्रवासन को प्रबंधित करने के लिए अच्छे से सोच-विचार कर योजना बनाने, कौशल विकास करने और आर्थिक अवसर वितरण की आवश्यकता होती है।

लंबित राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी

कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

जिला कलक्टर ने दिये मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिये हैं। सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व अधिकारी भू-रूपांतरण सहित राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करें, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके। इसके लिए सभी राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करें एवं लक्ष्य हासिल करने के लिए सप्ताह में पांचों दिन कोर्ट लेकर ज्यादा से ज्यादा दावों की सुनवाई करें। बैठक में कलक्टर ने जिले में भू-आवंटन, औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-संपरिवर्तन, नामान्तरण, सीमाज्ञान, कुर्रेजात, पत्थरगढ़ी एवं सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व संबंधी सभी प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारित करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने पटवारियों की कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदार को पटवार कार्यालयों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिये। इस दौरान कलक्टर ने अधिकारियों को पौधारोपण महाअभियान से संबंधित तैयारियों एवं व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने मानसून सीजन के दौरान उपखण्ड में आपदा प्रबंधन के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिये। उन्होंने जलभराव की स्थिति में जल निकासी एवं आमजन को रेस्क्यू करने के लिए जरूरी इंतजाम दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय रहते रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने के लिए पाबंद करें ताकि बारिश के दौरान आपदा प्रबंधन किया जा सके। बैठक कलक्टर ने अधिकारियों को जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र लंबित प्रकरणों के भी निस्तारण के निर्देश दिये। साथ ही, उन्होंने कहा कि पेंशन संबंधी प्रकरणों का भी निस्तारण के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही, रात्रि चौपाल एवं दौरों का विवरण संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण कर आमजन को राहत देने के निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) लोकेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू गोपाल परिहार सहित जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य राजस्व अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

केंद्रीय बजट सर्वजन हितैषीः डॉ. एस एस अग्रवाल

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉ. एस एस अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को सर्वजन के लिए हितैषी और फायदेमंद बताया है। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बजट में कर प्रणाली के सरलीकरण और लचीले बनाने से कर दाताओं की संख्या बढ़ेगी और देश के विकास को गति मिलेगी। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक रहे डॉ. अग्रवाल ने बजट में कैंसर की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी घटाने और इस बीमारी के इलाज में काम आने वाले उपकरणों पर लगने वाले टैक्स में कमी करने का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से इस भीषण बीमारी से जूझने वाले मरीज और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य कल्याण रूप और राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के अध्यक्ष डॉ. एस. एस. अग्रवाल ने शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं की सराहना की।

केन्द्रीय बजट से देश को मिलेगी ऊर्जा सुरक्षा- ऊर्जा मंत्री

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट को आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष-2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प की सिद्धि में सहायक होगा। नागर ने कहा कि इस बजट के माध्यम से केन्द्र सरकार ने देश में सभी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 9 चुनिंदा सेक्टर्स का महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में चयन किया है। इनमें ऊर्जा सुरक्षा को सम्मिलित करना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किस ठोस विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से देश के एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के संकल्प की पुनः अभिव्यक्ति और इसे आगे भी प्राथमिकता देने, विद्युत भंडारण को बढ़ावा देने के लिए पम्प स्टोरेज नीति, छोटे एवं मॉडयूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अनुसंधान तथा विकास, अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ देश में ही विकसित की गई एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की स्वदेशी तकनीक पर आधारित ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा सोलर सैल एवं सोलर पैनल के निर्माण में काम आने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची को विस्तार देने जैसी घोषणाएं भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होंगी।

सफाई मित्र क्षमता संवर्धन कार्यशाला व सम्मान समारोह आयोजित

द पुलिस पोस्ट

जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार "सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ" अभियान के तहत मंगलवार को मुरलीपुरा जोन में समस्त सफाई मित्रो का प्रशिक्षण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रो का सम्मान किया गया। उपायुक्त रेखा मीणा ने बताया कि सफाई मित्र क्षमता संवर्धन कार्यषाला एवं सम्मान समारोह का आयोजन हर जोन में किया जा रहा है जिसके तहत मंगलवार को मुरलीपूरा जोन में यह कार्यक्रम रखा गया। जिसमे सफाई मित्रो को कार्य के दौरान पीपीई किट का कैसे इस्तेमाल करते हुए खुद की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना है और बारिश के समय कैसे सफाई करना चाहिए इस हेतु PIU Team द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया इसके साथ ही सफाई के दौरान अपने कार्य को उत्कृष्ट तरीके से करने वाले सफाई मित्रो का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जोन के सीएसआई, एसआई एवं समस्त सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।

गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार बढ़ाने पर विचार -गोपालन मंत्री

द पुलिस पोस्ट

जयपुर गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपाहिज गौवंश को 12 माह का और शेष गौवंश को 9 माह का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। कुमावत ने कहा कि गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत गौ सेस एवं वर्ष 2018-19 से शराब बिक्री पर 20 प्रतिशत गौ सेस लगाया गया। इससे प्राप्त निधि से गौशालाओं को सहायता राशि और गौशालाओं के विकास के लिए संचालित योजनाओं के लिए राशि दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुल आय 1227.45 करोड़ रूपये हुई, जिसमें स्टाम्प ड्यटी से 596.41 करोड़ रूपये और शराब वैट से 631.4 करोड़ रूपये की आय शामिल थी और 1122.86 करोड़ रूपये व्यय हुआ। गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी गौशालाओं में अपाहिज नंदी और गौवंश को लेने का प्रावधान है। अपाहित गौवंश के लिए अलग से गौशालाएं निर्धारित नहीं हैं। इससे पहले विधायक अर्जुनलाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोपालन मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्तमान में कुल 54 गौशालाएं संचालित है जिनमें से 50 पंजीकृत एवं 04 अपंजीकृत गौशालाएं हैं। उन्होंने गौशालाओं की सूची मय पता, पशुधन संख्या तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण हेतु 39 पात्र गौशालाओं को दी गई कुल सहायता राशि रूपये 14 करोड़ 88 लाख 86 हजार 400 रु का विवरण सदन के पटल पर रखा। गोपालन मंत्री ने बताया कि चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रूपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिये जाने का प्रावधान है।

माण्डल क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं की शिकायतों की जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी - पंचायतीराज मंत्री

जयपुर पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र माण्डल की जिन ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। पंचायतीराज मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक उदयलाल भडाणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायतीराज मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र मांडल के अन्तर्गत पंचायत समिति मांडल, करेड़ा एवं सुवाणा तथा इनकी ग्राम पंचायतों के विगत 03 वर्षों के आय एवं व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि संबंधित वर्षवार आय में वर्ष का प्रारम्भिक शेष सम्मिलित नहीं है। जिस वर्ष किसी मद में आय से अधिक व्यय हुआ है, आधिक्य व्यय का भुगतान वर्ष के प्रारम्भ में शेष रही राशि से किया गया है। उन्होंने पंचायत समिति माण्डल, करेड़ा एवं सुवाणा में प्राप्त आय के विरूद्ध प्रमुख मदों पर किये गये व्यय का विस्तृत विवरण भी सदन के पटल पर रखा।

राज्य सरकार राजस्थान को 'हरित प्रदेश' के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध,

वन आच्छादित क्षेत्र को साल 2028 तक 20 हजार हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा,

मिशन 'हरियाळो राजस्थान' के तहत अगले पांच साल में 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे- वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को 'हरित प्रदेश' के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र को साल 2028 तक 20 हजार हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। मिशन 'हरियाळो राजस्थान' के तहत अगले पांच साल में लगभग 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शर्मा सोमवार को विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग (मांग संख्या-45) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने वन एवं पर्यावरण विभाग की 18 अरब 57 करोड़ 60 लाख 25 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने कहा कि वनों के लिहाज से प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। प्रदेश का दो तिहाई भाग मरूस्थल है। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र महज 9.60 प्रतिशत है। राज्य सरकार का लक्ष्य 20 प्रतिशत भू-भाग को वनाच्छादित करने का है। शर्मा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान' की शुरूआत की है, जिसके तहत प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में मातृ वन की स्थापना भी की जाएगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में वन आच्छादन क्षेत्र 16 लाख 65 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें 2028 तक 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि कर 16 लाख 85 हजार 400 हेक्टेयर तक लाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्रम को सतत् रखने के लिए बजट में मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम के रूप में मिशन 'हरियाळो राजस्थान' की घोषणा भी की गई है। शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की 40 प्रतिशत घोषणाएं अधूरी रहीं। इन घोषणाओं को अब वर्तमान राज्य सरकार 100 फीसदी पूरा करेगी। प्रदेश में 10 करोड़ पौधे तैयार किये जाने के लक्ष्य के मद्देनजर 50 नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, वर्तमान में संचालित हो रही 540 नर्सरियों का संवर्धन किया जाएगा। पौधों के संरक्षण के लिए 2000 स्थानीय लोगों को इन्सेन्टिव के आधार पर वन मित्र नियुक्त किया जाएगा। 175 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से प्रत्येक जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क विकसित किये जाएंगे। जयपुर के झालाना में 40 करोड़ रूपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में बाघों की संख्या 133 हो गई है, जो कि अब तक की सर्वाधिक है। अकेले सरिस्का टाइगर रिजर्व में पिछले 6 महीने में 13 शावकों का जन्म हुआ है जिससे यहां बाघों की अब तक की सर्वाधिक संख्या 43 हो गई है। शर्मा ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए इस वर्ष के आरंभ में 15 से 31 जनवरी तक संयुक्त अभियान चलाकर 202 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 181 एफआईआर दर्ज कर 97 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 1530 टन खनिज के साथ 162 वाहन जब्त कर 12 लाख रुपए का मुआवजा वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में साप्ताहिक रूप से कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 1 फरवरी से 31 मार्च, 2024 के मध्य 292 वाहन जब्त कर 67 लाख रुपए तथा 1 अप्रेल से 30 जून, 2024 के बीच 285 वाहन जब्त कर 55 लाख रुपए का मुआवजा वसूला गया।

"एक स्वर- एक समय" राष्ट्रीय गान कारगिल युद्ध के रन बाकुरों को सच्ची श्रद्धांजलिः कर्नल देव आनंद

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। जयपुर कारगिल युद्ध विजय के 25 वर्ष से गांठ के अवसर पर 'एक स्वर- एक समय" पर राजस्थान की हर स्कूल में राष्ट्रीय गान का ऐतिहासिक गायन रखा जाएगा । राष्ट्रीय गान के माध्यम से अपने जीवन का बलिदान देने वाले 527 वीर पुत्रों को श्रद्धांजलि दिए जाने के राष्ट्रीय शहीद सम्मान समिति की ऐतिहासिक पहल के आग्रह को राजस्थान सरकार द्वारा समर्थन के के लिए कर्नल देव आनंद ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का धन्यवाद किया। राष्ट्रीय शहीद सम्मान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद गुर्जर ने मीडिया बंधुओ से रूबरू होते हुए बताया कि कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में "राष्ट्रीय शहीद सम्मान समिति" कारगिल युद्ध मैं अपने जीवन का बलिदान देने वाले 527 वीर पुत्रों को नमन करने हेतु 11:25 मिनट पर 26 जुलाई 2024 के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर 1 मिनट का मौन एवं राष्ट्रीय गान के गायन का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक , विद्यार्थी एवं नागरिक अपने सबसे नजदीकी स्कूल या वार मेमोरियल पर पहुंच कर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ईस कार्यक्रम के माध्यम से देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के समर्थन में एक संदेश देने का प्रयास है कि, हमारे राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हर वीर सैनिक एवं वीर नारीयो के साथ देश सदैव खड़ा है। शहीद सम्मान समिति इस कार्यक्रम को गत 3 वर्षों से अपने-अपने स्तर पर स्थानीय शिक्षण संस्थानों के सहयोग से हर वर्ष करती रही है । कर्नल ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के हर युवा एवं नागरिक को कारगिल के वीर पुत्रों की नमन कार्यक्रम में जोड़ने हेतु देश के विभिन्न राज्यों से आग्रह किया गया है। उम्मीद है आने वाले दो-तीन दिनों में राजस्थान की तर्ज पर दूसरे प्रदेश भी अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर पुत्रों के सम्मान में इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए सदैव कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारगिल युद्ध में अपने जीवन का बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में 26 जुलाई को 11:25 पर 1 मिनट का मौन तथा राष्ट्रीय गान का 'एक स्वर- एक समय" आयोजन किए जाने के दिशा निर्देश के उपरांत प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक एवं नागरिकों में गर्व की अनुभूति का एहसास देखा जा सकता है । थोड़े दिनों पहले इस कार्यक्रम के बैनर का विमोचन करते हुए राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी ने कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में इस ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करने की बात कही थी । यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्यक्रम अपने तरीके का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें करोड़ों की संख्या में देश के युवा एवं नागरिक अपने सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय गान का आयोजन करने जा रहे हैं। देश के हर नागरिक से 26 जुलाई के दिन अपने-अपने निवास स्थान के निकट स्कूल या युद्ध स्थल या सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होकर 11:25 मिनट पर देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर पुत्रों की याद में राष्ट्रीय गान गाकर एकता का संदेश दे।

डायलिसिस मशीनें महंगे दामों पर खरीदने संबंधी शिकायत की जांच करवाई जाएगी -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आरएमएससीएल द्वारा डायलिसिस मशीनें महंगे दामों पर खरीदने संबंधी शिकायत की ऑडिट व जांच करवाई जाएगी और जांच में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएमएससीएल द्वारा डायलिसिस मशीनें व अन्य उपकरण महंगे दामों पर नहीं खरीदे गये हैं। उपकरणों की जांच के दौरान भी उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि फिर भी शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने जानकारी दी कि डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए चार बार निविदा आमंत्रित की गई। अंतिम बार आमंत्रित निविदा पर दो फर्मों, अपरा इंजीनियरिंग लिमिटेड व रीवा फार्मास्यूटिकल द्वारा आवेदन किया गया। रीवा फार्मास्यूटिकल को अधूरे दस्तावेज तथा पूर्व में शिकायतें होने के कारण अयोग्य मानते हुए अपरा इंजीनियरिंग लिमिटेड को उपकरण खरीद का टेण्डर दिया गया। इस फैसले के विरूद्ध रीवा फार्मास्यूटिकल द्वारा दो बार अपील भी की गई थी, जो सुनवाई के बाद रद्द कर दी गई। उन्होंने बताया कि पहली निविदा को कोई भी बिड़र सही नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किया गया। इसमें केवल उपकरणों के निर्माता अथवा आयातक से ही माल लेने का प्रावधान रखा गया था। इसके बाद 23 अगस्त, 2022 को डायलिसिस मशीन, आर ओ, एसी एवं आईसीयू बेड की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें किसी भी बिड़र ने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर, 2022 को तीसरी बार निविदा आमंत्रित की गई। चूंकि पूर्व की निविदा में किसी बिड़र ने रूचि नहीं ली इसलिए इस बार निर्माता, आयातक, आथोराइज्ड डीलर और वितरक चारों को आमंत्रित किया गया। इसमें डायलिसिस मशीन, आर ओ, एसी, आईसीयू बेड को एक साथ जोड़ कर निविदा आमंत्रित की गई थी, परन्तु यह बिड़ भी निरस्त हो गई। इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आरएमएससीएल द्वारा डायलिसिस मशीनें व एनिमिया कार्ड महंगे दामों पर नहीं खरीदे गये हैं। डायलिसिस मशीन व आर ओ सिस्टम 18 अप्रेल, 2023 को खुली निविदा के माध्यम से टर्न-की आधार पर 364 डायलिसिस मशीन व 182 आरओ सिस्टम हेतु निविदा आमंत्रित की गई। आरटीपीपी एक्ट 2012 व आरटीपीपी रूल्स 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाये जाने के पश्चात 04 अक्टूबर, 2023 को स्व। जारी किया गया। उन्होंने बताया कि एनीमिया कार्ड (सिकल सैल कार्ड) रूपये 27 सितम्बर, 2023 को खुली निविदा के माध्यम से 35 लाख सिकल सैल कार्ड हेतु निविदा आमंत्रित की गई। आरटीपीपी एक्ट 2012 व आरटीपीपी रूल्स 2013 के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपकरणों के क्रय से पूर्व उपकरणों की दरों का बाजार सर्वे करवाने के पश्चात दरें औचित्यपूर्ण पाए जाने के पश्चात 11 दिसम्बर, 2023 को स्व जारी किया गया।

रामनिवास बाग से घाटगेट आगरा रोड घाट की घूणी, ट्रान्सपोर्ट नगर दिल्ली वाईपास रोड ईदगाह तक रोंड के दोंनों तरफ करीब 7 कि.मी. तक तक अवैध निर्माण हटाए

द पुलिस पोस्ट

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-1, 2 व 10 में रामनिवास बाग से घाटगेट आगरा रोड घाट की घूणी, ट्रान्सपोर्ट नगर दिल्ली वाईपास रोड ईदगाह तक रोंड के दोंनों तरफ करीब 7 कि.मी. तक अवैध निर्माण हटाए। जोन-5 व पीआरएन नोर्थ में ओम होटल से 200 फीट वाईपास होते हुए पुरानी चुंगी अजमेर रोड तक के एरिया में आज करीब 140 अतिक्रमणों को हटवाया। लगातार कार्यवाही करते हुये कुल 1285 अवैध कब्जों-अतिक्रमणों को हटवा कर रोड सीमाओं को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जयपुर शहर के मुख्य रोड्स, सेक्टर रोड्स व अन्य रोड्स पर बाधित यातायात आवागमन को सुगम संचालन हेतु सड़कों पर अस्थायी रूप से किये जा रहे अवैध कब्जों-अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा दिनांकः 15. 07. 2024 से शुरू की गई। जिसमें आज दिनांकः 23.07.2024 को रामनिवास बाग से घाटगेट आगरा रोड घाट की घूणी, ट्रान्सपोर्ट नगर दिल्ली वाईपास रोड ईदगाह तक रोंड के दोंनों तरफ करीब 7 कि.मी. तक के एरिया में करीब 120 अतिक्रमणों को हटवाया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देषन में मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देषन में उप नियंत्रक-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-1, 10, एस आई के सहयोग से सामुहिक अभियान का आयोजन कर रामनिवास बाग से घाटगेट आगरा रोड घाट की घूणी, ट्रान्सपोर्ट नगर दिल्ली वाईपास रोड ईदगाह तक रोंड के दोंनों तरफ करीब 7 कि.मी. तक के दायरे में दुकानों, मकानों के आगे अत्यधिक लम्बाई में बने चबुतरें, सीढ़ियां, बाउण्ड्रीवाल, लोहे के एंगिल टीनशेड, सीमेन्ट के पिलर, बांस तम्बू तिरपाल की झुग्गी झोंपडी, लगाये गये चाय, नास्तें की थडियां, ठेलें, रेलिंग, टेबल कुर्सियां, होर्डिंग-साइन बोर्ड इत्यादि द्वारा किये गये लगभग 120 स्थाई-अस्थाई अवैध कब्जों-अतिक्रमणों को जोन- 1, 2, 10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी, मजदूरों की सहायता से हटाया जाकर मुख्य रोड़ को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देषन में उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन-1, 10 एस आई, पुलिस लाईन से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस जाप्ता, स्थानीय पुलिस थाना का पुलिस बल तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। जेडीए द्वारा मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देषन में उप नियंत्रक-द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन- 06, पीआरएन (नॉर्थ), एस आई के सहयोग से सामुहिक अभियान का आयोजन कर ओम होटल से 200 फीट वाईपास होते हुए पुरानी चुंगी अजमेर रोड़ तक के दायरे में दुकानों, मकानों के आगे अत्यधिक लम्बाई में बने चबुतरें, सीढ़ियां, बाउण्ड्रीवाल, लगाये गये चाय, नास्तें की थडियां, ठेलें, तिरपाल, रेलिंग, टेबल कुर्सियां, होर्डिंग-साइन बोर्ड इत्यादि द्वारा किये गये लगभग 140 स्थाई-अस्थाई अवैध कब्जों-अतिक्रमणों को जोन- 5, पीआरएन (नॉर्थ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी, मजदूरों की सहायता से हटाया जाकर मुख्य रोड़ को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देषन में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन- 6, पीआरएन (नॉर्थ), पुलिस लाईन से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस जाप्ता, स्थानीय पुलिस थाना का पुलिस बल तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

यूआईटी भीलवाड़ा का नया कारनामा आया सामने,

अब तिलक नगर योजना के मुआवजे में आया घोटाला और भ्रष्टाचार का प्रकरण

ना गलत मुआवजे का,ना ही पत्रावली खोने का मुकदमा दर्ज करा रही यूआईटी,आखिर किसको बचाने का है प्लान...??

नगर विकास न्यास के घोटाले के पीछे आखिर कौन है सफेदपोश और अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार, कैसे बन गए यूआईटी के कर्मचारी अरबपति.......?

सरकार से बड़े कैसे हो गए यूआईटी भीलवाड़ा के ठेकेदार, अवैध भू कारोबारी और भू माफिया, यह कब जाएंगे सलाखों के पीछे.....?

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा तिलक नगर योजना में राजस्व ग्राम भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1659,1661,1662,1665,1666 कुल रकबा चार बीघा जो नगर विकास न्यास भीलवड़ा द्वारा अवाप्त कर प्रकरण संख्या 390/91 निर्णय दिनांक 26.08.1994 को किया गया। इसमें न्यास के भ्रष्ट अधिकारी व कार्मिक अपनी दूषित कार्यकलापो व दस्तावेजातो के चलते अपनी पुर्ति हेतु मिलीभगत कर 15 प्रतिशत का मुआवजा दिया गया। मौका स्थिति पर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का एक इंच भी कब्जा नही होकर खातेदार को प्रतिफल स्वरूप मुआवजा गलत भ्रामक व दूषित कृत्यो व कूट रचित दस्तावेजातो व अदृश्य कारणो के चलते दिया गया। क्योकि मुआवजा देते वक्त न्यास के अधिकारी व कार्मिको यह भलीभाति ज्ञात था कि मुआवजा तो गलत व बेबुनियाद है लेकिन मुआवजा देने पर अधिकारी व कार्मिको की लिप्त भुकारोबारीयो व भुमाफियाओ कि साठ गाठ के चलते अदृश्य बडी पुर्ति हो रही थी। उपरोक्त आराजियत नियमन कर पुर्व में ही आवाप्ति न्यास द्वारा कर ली गई थी, परन्तु पहले से ही खातेदार द्वारा कृषि भूमि पर कृषि भूखण्ड काट कर विक्रय कर दिये थे। इन सभी काटे गए कृषि भूखण्डो पर मकान बने हुए थे। जिसके बाद भी नियमन कर जमीन न्यास के नाम हो चुकी थी, व अवार्ड संख्या 390/91 दिनांक 18.01.2023 में न्यास द्वारा उक्त कृषि भूमि का पुनः मुआवजा दिया गया। न्यास भीलवाड़ा के अन्दर मुआवजे के बडे-बडे भ्रष्टाचारी कांड वेसे तो वर्ष 2011 से ही हो रहे है लेकिन बडी विडम्बना यह है कि वर्ष 2019 से लगाकर वर्ष 2023 तक न सोचने वाले मुआवजे, फर्जी पट्टे इत्यादि बनवाने व क्रियानवित कराने में कोन कोन भूमाफिया, भूकारोबारी,दलाल न्यास के अधिकारी व कार्मिक शामिल है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यास भीलवाड़ा में अनुमानित यह तीसरी कार्यवाही है लेकिन ऐसा क्या अदृश्य कारण है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अपने अन्तिम पडाव तक पहुचते पहुचते शून्य हो जाता है इससे ऐसा प्रतित होता है कि जॉच ऐजेन्सीयो से ज्यादा बलशाली व रसुकदार भूमाफिया, भूकारोबारी, दलाल, न्यास के अधिकारी व कार्मिक है। जिसके चलते किये कृतियो को छूपाने के लिये जॉच ऐजेन्सीयो की कार्यवाहीयो को भी विराम लगा देते है......? सबसे बडी विडम्बना यह है कि किये गए भ्रष्टाचारी कार्यो कि पत्रावलिया न्यास भीलवाड़ा के रिकार्ड से गायब होने के बाद व दिखती हानि सरकार के राजकोष को पहुचाने के बाद भी क्यो निवर्तमान व वर्तमान अधिकारी एफआईआर दर्ज कराने से डरते व कतराते है जिसके चलते रसुकदार भूमाफिया, भूकारोबारी, दलाल, न्यास के अधिकारी व कार्मिक के होसले बुलन्दीयो पर होकर अल्प समय में ही अकूक सम्पति के मालिक हो गये जिससे आमजन को तो कार्य करवाने में चक्कर पे चक्कर लगाने पडते है फिर भी कार्य नही होता है लेकिन भूकारोबारीयो और भूमाफियाओ का क्षणिक समय में काम हो जाता है। कृषि भूमि आराजी नम्बर 1659,1661,1662,1665,1666 कुल रकबा चार बीघा के प्रतिफल स्वरूप न्यास ने तिलक नगर के मुख्य मुख्य मार्गो पर बडी बडी रोडो पर बेशकिमती कोर्नर के बडे बडे भूखण्ड दिये जिनकी संख्या कुल 05 है मिली सूत्रो व नाम न बताने की स्थिति में जानकारी अनुसार दिये गये मुआवजे के 05 भूखण्डो में से दो भूखण्डो की रजिस्ट्री उप पंजीयत भीलवाड़ा के यहा हुई थी। सूत्रो का तो यहा तक कहना है कि न्यास के अधिकारी व कार्मिको की मन चाही अदृश्य लाभ पुर्ति न होने से न्यास के उच्च अधिकारीयों व लिप्त कार्मिको को मालूम चलते ही प्रकरण एफआईआर दर्ज करा रजिस्ट्री निरस्त करवा दी। लेकिन जो बडा बेशकीमती मुआवजा खातेदार को दिये जा चुका था उसकी वसूली की कोई कार्यवाही नही कि गई क्यो इसके पिछे क्या बडा अदृश्य राज था जो कि एक जॉच का बहुत बडा विषय है।

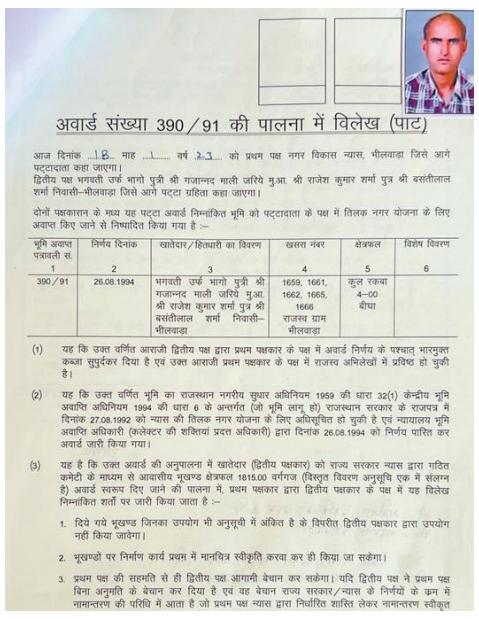

खतेदार भगवती उर्फ बागो पुत्री श्री गजान्नद माली जिसका मुखतियार नामा आम राजेश कुमार शर्मा पुत्र बंसती लाल शर्मा को निम्न भूखण्ड दिये थे।

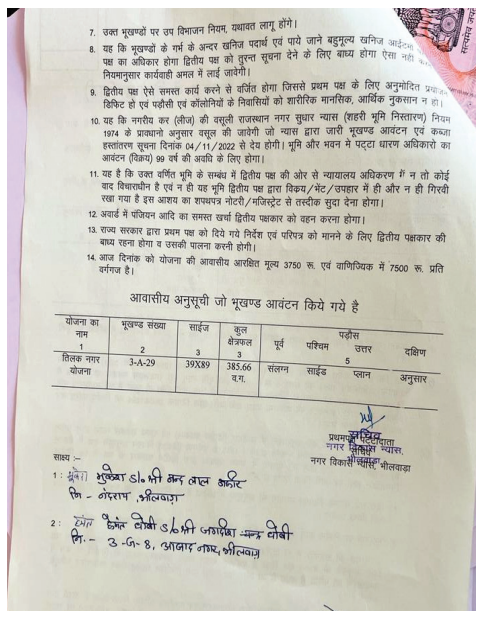

*01. 3-ए-1 साईज 39*89 (कोर्नर)*
*02. 3-ए-29 साईज 39*89 (कोर्नर)*
*03. 6-एफ-1 साईज 39*69 (कोर्नर)*

व अन्य भूखण्ड दिये गये। इस संदर्भ में मिली सुत्रो से जानकारी अनुसार भगवती उर्फ बागो पुत्री श्री गजान्नद माली नाम कि कोई वारिसान थी ही नही फिर भी किस रसुकदार भूमाफिया, भूकारोबारी,दलाल, न्यास के अधिकारी व कार्मिक ने सरकार के कोष को हानि पहुचाने के लिये व अपनी पुर्ति करने के लिए इतना बड़ा भ्रषटाचारी खेल खेला जो जॉच ऐजेन्सीयो व जिले के आलाधिकारीयो की जॉच का बड़ा विषय है

उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम ने कुछ दिनों पहले नगर विकास न्यास का रिकॉर्ड जब्त किया है। लोगों का कहना है की गहराई से जांच होगी तो दोहरे भुगतान के मामले भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सामने आ जाएंगे और इसके बाद कई बड़ी मछलियों की गर्दन एसीबी जांच में फंस सकती है। अब देखना होगा कि कितने दिनों तक बकरे की अम्मा खैर मनाती है। तिलक नगर के मामले में नगर विकास न्यास के लोगों का ही कहना है कि एसीबी की तर्ज पर ही अगले कुछ दिनों में यहां एक दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के पास यूआईटी भीलवाड़ा के कारनामे एक-एक कर पहुंच रहे हैं जिनकी सभी की जांच होना लगभग तय है ।

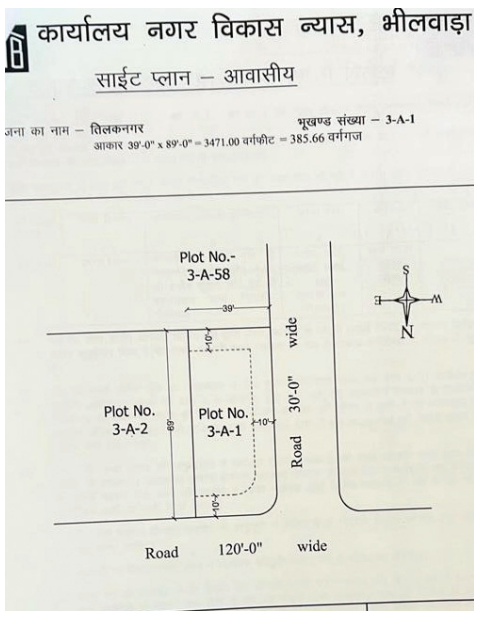

बेशकिमती कृषि बसी कॉलोनी का दिया बेशकिमती मुआवजा

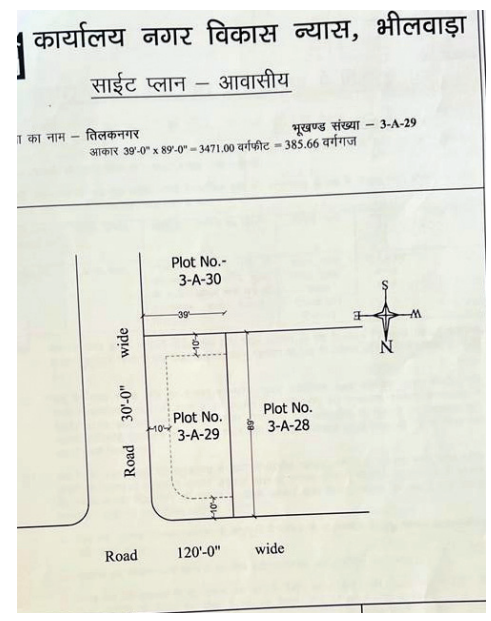

नगर विकास न्यास द्वारा राजस्व ग्राम भीलवाड़ा की आराजी संख्या 2214, 2215, 2216, 2217 कुल रकबा 5 बीघा तीन बिस्वा का 1/2 हिस्सा खातेदार धर्मेन्द्र सिंह शक्तावता पुत्र शिव सिंह शक्तावत का था जिन्होंने पूर्व में कृषि भूमि पर कृषि भूखण्ड विक्रय कर दिये थे और उन पर मकान बने होने के बावजूद नगर विकास न्यास से अवार्ड संख्या 129/91 दिनांक 30.01.2024 को पारीत करा कर मुआवजे के रूप में भूखण्ड संख्या 4-जे-43, 4-जे-44 क्षेत्रफल एक भूखण्ड का 3989 था जिनका कुल क्षेत्रफल 6 हजार 942 वर्ग फुट था जो मुआवजे के रूप में लेकर (अ) अर्पित पुत्र श्याम सुन्दर (ब) गोपाल झवर पुत्र प्रहलाद झवर (स) नरेन्द्र राठी पुत्र बालमुकन्द राठी को भूखण्ड संख्या 4-जे-43 का दिनांक 15.12.2023 को जरीये पंजीकृत बैचान बैचान कर दिया। भूखण्ड संख्या 4-जे-44 का धर्मेन्द्र सिंह शक्तावता पुत्र शिव सिंह शक्तावत द्वारा (अ) अर्पित बिडला पुत्र बालूराम बिडला (ब) कैलाश बद्रीलाल काबरा पुत्र बद्रीलाल जगन्नाथ काबरा (स) राकेश राठी पुत्र दामोदर राठी को कर दिया लेकिन राजस्व रेकॉड में अवाप्त भूमि नगर विकास न्यास के नाम इन्द्राज होने के बावजूद भी भौतिक कब्जा न्यास नहीं ले पाया है और मुआवजा जारी कर दिया है। ऐसा क्यों व किन कारणों से किया गया इसके पिछे कौन कौन है जॉच करा कड़ी से कड़ी विधि कार्रवाई क्यों नहीं की गई...? उक्त मुआवजा देने का सबसे बढ़ा कारण है कि मौके पर एक इंच भी जगह नहीं होने से कृषि भूमि के मलिक द्वारा कृषि भूखण्ड काट दिए और वहा पर मकाल बन गए के पश्चात मुआवजे की फाईल नगर विकास न्यास में लगाई गई और बेचे कृषि भूखण्डों को मुआवजा उठा लिया गया जो कि एक राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी का कृत्य है इस मुआवजे को स्वीकृत कराने के लिए नगर विकास न्यास के किस किस अधिकारी ने किस किस कार्मिकों के जरिए हस्ताक्षर कर भुगतान किया और मुआवजा स्वीकृत कराने में भीलवाड़ा के कौन कौन दलाल व सफेद पोश सामिल है। जो एक बहुत बड़ा रहस्यमही विषय है और यह बताता है कि नगर विकास न्यास में इस तरह के दूषित और भ्रष्टाचारी कृत्य कितने लम्बे समय से चल रहे है। जिससे सरकार के राजस्व को बड़ी हानी हो रही है और इस तरह की कई पत्रावलियां भी गायब है जिसके लिए भी संबंधित आलाअधिकारी व कार्मिक मौनमुख दर्शक बने हुए है...?

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक संपादक उपेन्द्रसिंह राठौड़, अम्बर ऑफसेट प्रा लि डीएल टॉवर, 3ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र जेएलएन मार्ग जयपुर से मुद्रित एवं भू-तल ऑरबिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित, 99280-96524, पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार, अनिल मलिक (सहसंपादक) 8696750000, पंकज गर्ग (प्रबंध संपादक) 01482-455184, 9214417111